bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org
संवत 2079 युगाब्द 5124 कुल पृष्ठ –32 अंक – 23

वर्तमान कमल ज्योति

₹10

राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नामांकन

राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का लखनऊ स्वागत

प्रदेश पदाधिकारी बैठक, लखनऊ

रामपुर व आजमगढ़ संसदीय उपचुनाव में जीत की बधाई

वर्तमान

कमल ज्योति

संरक्षक

श्री स्वतंत्र देव सिंह

सम्पादक

अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध सम्पादक

राजकुमार

प्रकाशक

प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक

ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग

लखनऊ – 1

फोन :– 0522–2200187

फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

सत्य मेव जयते

नवीन संसद भवन के शिखर पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय चिन्ह का मा० नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अनावरण

सम्पादकीय

सरकार की उपलब्धियां और विकास का मार्ग

राष्ट्रसेवा कांटो भरी राह है। यह अग्निपथ पर संचलन का कार्य है। महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध कविता में इसे ''अग्निपथ के पार चन्दन चांदनी का देश'' कहा गया है। हम इस राष्ट्र की मिट्टी के कण—कण को चन्दन मानते हैं। इसे इसी महक से सुवासित करना चाहते हैं। फिर राजनीतिक क्षेत्र का कार्य तो प्रतिपल कांटो भरा ही है। मंच माला, माइक और प्रपंच राग और द्वेष में बढ़ोत्तरी करते हैं। पद और कद आकर्षित करते हैं।

इसीलिए,

पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि ''हमको यह सोचना चाहिए' कि हम सब अब तक की दुनिया की प्रगति में अपना क्या योगदान कर सकते हैं। हमें स्वयं को स्वार्थी होने से बचाना होगा ताकि हम संपूर्ण विश्व की प्रगति में सहभागी बनें'।

पंडित जी का एकात्म दर्शन और अंतिम व्यक्ति के कल्याण का लक्ष्य हमारा विराट सपना है। प्राचीन भारत से नए भारत की ओर बदलने का प्रयास इसी पंचनिष्ठांओं, नीतियों, एवं सिद्धान्तों का दर्शन है। हम किसी विदेशी राजनीतिक धारा से नहीं जन्में हैं। हमारे सपने विराट हैं। संकल्प को शक्ति और शक्ति को कर्म में बदलने का मर्म हमें ज्ञात है।

ऐसी परिस्थितियों में भाजपा का विराट लक्ष्य और सम्यक विचार हमें दिशा देता है। पिछले कई दशकों में पार्टी ने भारतीय जनजीवन के अनेक ज्वलंत प्रश्नों का समाधान इसी वैचारिक अधिष्ठा्न से प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्यों को सम्मुख लाकर केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'अन्त्योदय' और 'एकात्ममानव' की आधारशिला को मजबूत किया है। संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस हेतु सतत प्रयत्नशील हैं।

अपनी दूसरी पारी के प्रथम 100 दिनों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास के नारे को जमीन पर उतारने में पूरी सफलता पाई है। गांव, किसान, शहर, उद्योग, सामाजिक समसरता, पर्यटन से लेकर अध्यात्म तक हर मोर्चे पर प्रदेश ने प्रगति के प्रतिमान स्थापित किए हैं। सही अर्थों में सरकार को कार्य कैसे करना चाहिए इसका अप्रतिम उदाहरण योगी सरकार ने प्रस्तुत किया है। अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम दिन से सरकार ने उम्मीदों को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू की। मुख्यमंत्री ने खुद सभी विभागों का प्रजेंटेशन देखा और विभागवार चुनौतियों, जरूरतों और लक्ष्यों की भूमिका तैयार की।

चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं द्वारा मिले सपोर्ट के बाद सरकार ने अपना ध्यान सबसे अहम चुनौती पर केंद्रित किया, वह थी—कानून व्यवस्था। सुशासन के लिए यहां कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत थी। उसको उठाया गया। सरकार गठन के दो महीने के अंदर ही ग्रांउड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत सरकार ने तीसरी बार 80 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये।

यूपी के बढ़ते कदम ने इसे वैश्विक अवसरों के केंद्र के रूप में बदल दिया। बुनियादी सुविधाओं से लेकर उद्योग तक गांव से लेकर शहर तक, किसान से लेकर कामगार तक, छात्र से लेकर नौजवान तक, गरीब, वंचित सहित समाज के हर हिस्से को मुख्यधारा में खड़ा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक 5.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां नौजवानों को उपलब्ध कराया गया है। मध्य यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना से प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया होने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उदघाटन को तैयार है।

akatri.t@gmail.com

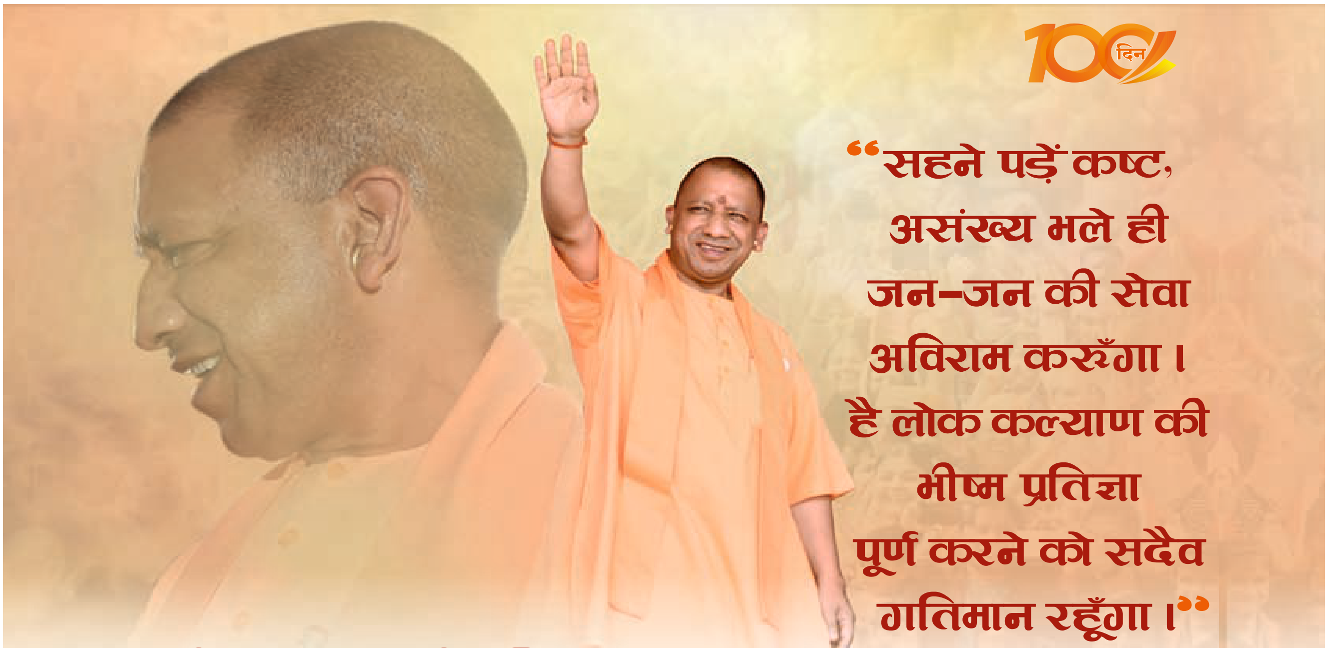

जो कहा सो किया...

उत्तर प्रदेश नई उड़ान के साथ यात्रा पूरा कर रहा : योगी

साधक राजकुमार

संकल्प से सिद्धि तब मिलती है जब मनसा, वाचा, कर्मणा के साथ पवित्र भाव से कर्म को किया जाता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में दूसरी बार योगी सरकार ने शपथ के साथ सौ दिन के कार्य का लक्ष्य तय किया था जो चरणबद्ध पूरा हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास के अन्त्योदय संकल्प पर चलते हुए योगी सरकार लोक कल्याण की प्रतिज्ञा को पूरा कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिनाई। लोक भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र सहित प्रमुख लोगों की उपस्थिति में 100 दिन के कामकाज को जनता के सामने रखा।।

भाजपा नीत गठबंधन की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के 100 दिन के कार्यकाल की पहली प्रेस वार्ता में सबका स्वागत करता हूं। प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और निर्देशन में भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर विश्वास जताया। वह विश्वास निरंतर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए 36 में से 33 सीट पर जीत हुई। विधानपरिषद का सदन पहली बार कांग्रेस मुक्त हो गया। इसके बाद दो लोकसभा चुनाव भी सम्पन्न हुए। पूर्वी, पश्चिमी की दोनों सीटे रामपुर, आजमगढ़ दोनों सीट पर भाजपा को आशीर्वाद मिला। प्रधानमंत्री के बेहतर समन्वय का परिणाम है, जिसके कारण जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 100 दिनों के कार्यकाल में सरकार ने अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित की, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई **"वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी"** का 5 वर्षों का लक्ष्य पूरा होने के आसार दिख रहा है बेरोजगारी की दर 2017 में जहां 17.5 प्रतिशत थी। अब वह घटकर 2.9 प्रतिशत पर आ गयी है।

सीएम ने कहा कि उत्तरप्रदेश के इतिहास में 37 वर्ष बाद ये समय आया कि एक सरकार को दोबारा प्रचंड बहुमत मिला और किसी मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया। उत्तर प्रदेश देश की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं है, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में बेहतर कर सकता है।

हमारा दूसरा कार्यकाल जो जनता ने दिया है, हम उस यात्रा को नई उड़ान के साथ पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। हमने दोबारा आने के बाद पूरी व्यवस्था को दस सेक्टर में बांटकर कार्य शुरू किया। मंत्रियों ने प्रजेंटेशन स्वयं बनाया और मंत्रिमंडल के सामने समीक्षा हुई। मुझे प्रसन्नता है सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को हमारे 18 मंत्री समूहों ने सभी कमिश्नरी में कैम्प किया। जनपद स्तर, ग्राम स्तर तक गए, जनता चौपाल के कार्यक्रम के आयोजन हुए। मंत्रिसमूह अब तक दो-दो कमिश्नरी का भ्रमण कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि ये सारे कार्यक्रम उत्तरप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए टीमवर्क की तरह काम किये जा रहे हैं। हमने 5 वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ ने 100 दिन की प्रगति को प्रस्तुत कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने तकनीकी का उपयोग किया। पहली बार सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-पेंशन कार्यक्रम लागू किया। देश का पहला राज्य बना। कहा

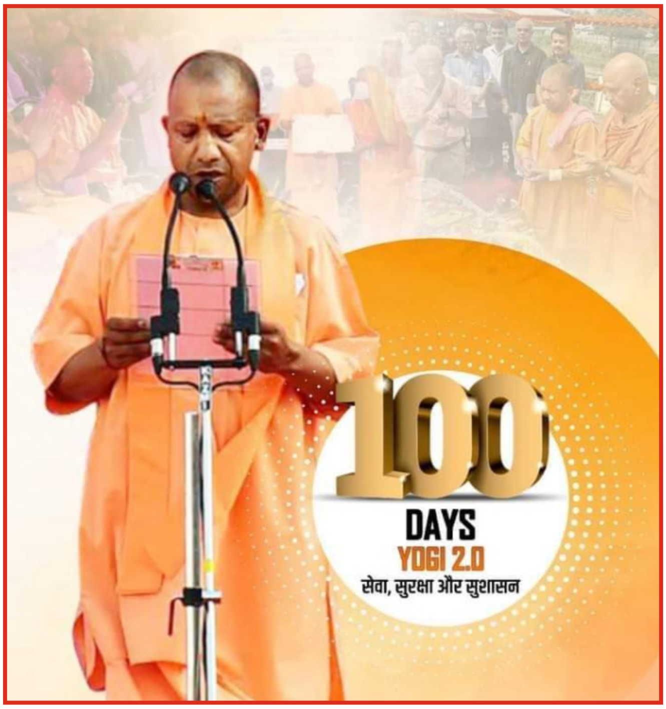

कि ई–विधान लागू हुआ। आखिर सत्र इसी कार्यक्रम पर आयोजित हुआ। राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये 100 दिन के भीतर कार्य हुए हैं।

सीएम ने कहा कि पहले प्रदेश, परिवारवाद, दंगो, अराजकता के लिए जाना जाता था, 2017 के पहले प्रदेश में पहचान की संकट थी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की राज्य सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं होती थी। हमने 5 वर्ष में कानून का राज़ स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश आये, अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया। हमने 100 दिन में 847 करोड़ की सम्पत्ति जब्त की गई है। अवैध पार्किंग, अवैध टैक्सी स्टैंड हटाये गए। प्रदेश भर से 68 हजार से अधिक अवैध अतिक्रमण स्थल हटाये गए।

सीएम ने कहा कि पहली बार धर्मस्थलों से माइक हटाये गए, 1–लाख से अधिक माइक को हटाया गया या उनकी ध्वनि को कम किया गया। आज सड़कों पर कोई भी कार्यक्रम नही होते, अलविदा की नमाज़, ईद की नमाज सड़क पर नहीं होते। कहा कि पाक्सो एक्ट अंतर्गत महिला, बालिकाओं के अपराधियों को प्रभावी पैरवी करते हुए सज़ा दिलाई गई। प्रदेश में आज हर तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना की ओर अग्रसर है, अगले 2 वर्ष में विश्वास है कि ये पूरा हो जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में दोगुनी वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हुई, बजट भी दोगुना हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले ही बजट में लोककल्याण संकल्प पत्र के 130 में से 97 संकल्पों को पहली बजट में शामिल किया। कहा कि शेष 37 संकल्प अगले वर्ष में शामिल करेंगे। दशकों बाद प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना, ये 2017 के पहले सपना था,100 दिन के अंदर 80000 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा हुआ है। प्रदेश में पहली बार डाटा सेंटर हब बन रहा है, आज प्रदेश में 4 नए डाटा सेंटर बन रहा है, इसमे 4 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने के संभावना है।

सीएम योगी ने कहा कि हमने औद्योगिक विकास के कार्यक्रम आगे बढाते हुए, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हमने 2018 में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया, आज उस का परिणाम हैं कि 16,17% की तुलना में बेरोजगारी घटकर 2. 9% तक रह गया है। एक जिला एक उत्पाद से प्रदेश में एक्सपोर्ट का हब बना, 1 लाख 56 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सहभागिता की, इसके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। ऋण मेला के माध्यम से स्वतः रोजगार के लिए ऋण वितरित किये जा रहे हैं। 17 लाख युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट दिए गए, खिलाड़ियों के लिए राजपत्रित नौकरी की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि संकट के समय सरकार आम जनमानस के साथ खड़ी है हम उज्ज्वला लाभार्थियों को होली, दीवाली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त देने का कार्य कर रहे है, यह 100 दिन भीतर हुआ। कहा कि कन्या सुमंगला योजना में 1 लाख नई बालिकाओं को जोड़ा गया, अब तक कुल 13 लाख से अधिक कन्याएं लाभान्वित हो रही है। महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश की आधार हैं, हम उन्हें 400 करोड़ रुपये का फंड दे रहे हैं, यह भी 100 दिन भीतर हुआ है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ग्राम सचिवालय की परिकल्पना साकार हो रही है, उन्हें इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी प्रदेश में नियंत्रित है, पिछले 100 दिन में 2 बार संचारी रोग उन्मूलन अभियान शुरू हुए हैं। दिमागी बुखार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जनपद प्रभावित थे, 2017 तक 50 हजार से अधिक बच्चों की मौतें हुई, अब हमने इसके उन्मूलन की ओर अग्रसर हैं। कहा कि कल प्रदेश भर में वन महोत्सव के माध्यम से 25 करोड़ वृक्षारोपण करने की ओर प्रयास करेंगे, इसे आगे करते हुए 35 करोड़ वृक्षारोपण करने की ओर अग्रसर होंगे।

योगी सरकार द्वारा प्रदेश में अमन चैन सुशासन सुरक्षा के नये कीर्तिमान सीपित करते हुए **"अपराध और अपराधियों"** के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कानून व्यवस्था से खेलने वालों के खिलाफ त्वरित कठोरतम कार्यवाई की गयी।

सब मिलकर उत्तर प्रदेश में नई–नई चुनौतियों के बाद भी योगी सरकार अपनी नई सोंच और अनथक परिश्रम के जिस मार्ग पर बढ़ रही है वह उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में कारगर साबित होगी। इस सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल में नई दिशा, नई सोंच, नई जन प्रतिबद्धता, नेक इरादे कुछ वर्षों में प्रदेश को देश में नई पहचान दिलायेगा।

संकल्प! पेड़ लगायें, उन्हें बचायें : योगी

आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष **''वृक्षारोपण जन आन्दोलन 2022''** के अन्तर्गत लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में सरकार – संगठन आम जन ने उत्तर प्रदेश में सक्रिय सहभागिता प्रयास के आधार पर इतिहास रचते हुए फलदार, औषधिय पौधों का रोपण कर उनके सुरक्षा, सरंक्षण का भी संकल्प लिया। एक ही दिन में 25 करोड़ 15 लाख 12 हजार 943 पौधों का रोपण कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की गई है, जबकि 25 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य था।

माननीय राज्यपाल महोदयाएवं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश ने पौध रोपित कर वृक्षारोपण जन–आन्दोलन 2022 के अन्तर्गत एक ही दिन में 25 करोड़ पौध रोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारम्भ दिनांक 05.07.2022 को माननीय राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश श्रीमती आनन्दीबेन पटेल द्वारा कुकरैल वन क्षेत्र, लखनऊ में किया गया। वन महोत्सव में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा त्रिशक्ति के रूप में माँ पार्वती के स्वरूप में कदम्ब, माँ दुर्गा के स्वरूप में नीम तथा माँ सरस्वती के रूप में आम के वृक्ष का रोपण किया गया। माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अपने सम्बोधन में उत्तर प्रदेश सरकार के इस महा अभियान की सराहना करते हुये जन सामान्य से सहयोग की अपेक्षा करते हुये प्रत्येक नागरिक से कम से कम 5 पौधों के रोपण का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग के कार्यों की सराहना करते हुये यह सुझाव दिया कि प्रत्येक जनपद में नक्षत्र एवं राशि वन तथा बोनसाई गार्डेन एवं पंचतंत्र वाटिकाओं की स्थापना की जाये। माननीय राज्यपाल महोदया ने यह भी सुझाव दिया कि स्कूल के बच्चों को प्रारम्भ से ही प्रकृति से जोड़ने के लिये छोटे–छोटे पर्यावरण गीतों एवं कविताओं की रचना कर उन्हें स्कूलों में बांटा जाये, ताकि बच्चे उन्हें सीख सकें। माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने, जल संरक्षण हेतु चलाई जा रही अमृत सरोवर योजना एवं स्वच्छता अभियान की प्रशंसा करते हुये समस्त जन को इसमें सक्रिय सहयोग देने हेतु आह्वा्न किया गया।

वन विभाग द्वारा सुप्रसिद्ध लोकगायिका पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी को वृक्षारोपण अभियान का ब्राण्ड अम्बेसडर घोषित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही जी, राज्य मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश श्री के0पी0 मलिक जी, विधायक लखनऊ पूर्वी श्री आशुतोष टंडन जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, श्रीमती मालिनी अवस्थी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में माननीय कृषि मंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि पर पड़ने वाले दुश्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुये वृक्षारोपण की आवश्यकता तथा स्थानीय प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। उनके द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि कृषि विभाग आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। इस अवसर पर राज्यमंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री के0पी0 मलिक द्वारा यह अवगत कराया गया कि वन विभाग अपनी पूरी क्षमता से राज्य के वनावरण को बढाने का प्रयास कर रहा है तथा इस कार्य में सभी का सहयोग लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वृक्षारोपण अभियान की ब्राण्ड अम्बेस्डर के रूप में नियुक्त श्रीमती मालिनी अवस्थी द्वारा भारतीय संस्कृति में वृक्षों एवं वनों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुये अनेक लोक गीत सुनाये गये।

स्कूलों के बच्चों एवं एन0सी0सी0 के कैडेट्स द्वारा 2000 पौधों का रोपण कर वृक्षारोपण अभियान में भागीदारी की गई। नेशनल बैम्बू मिशन, उत्तर प्रदेश वन निगम, टर्टल सर्ववाईवल एलायन्स,

एच0सी0एल0 फाउन्डेशन तथा पृथ्वी इनोवेशन द्वारा अपने उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया।

मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चित्रकूट में हरीशंकरी का पौधा रोपित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्थानीय प्रजातियों के रोपण तथा रोपित पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पर बल दिया गया। समाज के हर वर्ग को वृक्षारोपण कार्यक्रम में आगे बढकर भाग लेने का संदेश दिया गया, जिससे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन आन्दोलन का रूप प्राप्त हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन शमन हेतु कार्बन अवशोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधों के रोपण का आह्वान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने **''मटदर वन ब्लॉक''** वन क्षेत्र को **''कोदण्ड वन''** के नाम से मूल प्राकृतिक स्वरूपमें संरक्षित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं के अथक मेहनत के बल पर पहरा वन ब्लॉक में 4 हे0 क्षेत्र में 40,000 पौधों का रोपण कर वन स्वरूप के रूप में स्थापित करने हेतु वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक (वाचर) एवं पर्यावरण प्रेमी भईया राम को शाल पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

वृक्षारोपण महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के साथ–साथ श्री अरूण कुमार, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पौधारोपण किया गया।

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदो में 50 कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री, 25 सांसदो तथा शासन के विभिन्न अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के समस्त अधिकारी सभी जनपदों में अभियान के नोडल अधिकारी के रूप में भाग लेते हुए पौधारोपण किया गया।

ग्राम वासियों की आय में वृद्धि हेतु ग्राम पंचायत की भूमि पर इमारती एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया।

वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत मुख्य प्रजातियां नीम, सहजन, आंवला, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुटेल, बांस, पीपल, पाकड़, बरगद आदि का रोपण किया गया।

फसलों में विविधता लाकर आय में वृद्धि हेतु कृषि वानिकी के अन्तर्गत कृषकों द्वारा वृहद स्तर पर रोपण कराया गया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कृषकों के द्वारा 1 से 10 पौधो का रोपण किया गया।

वर्ष 2022 के वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पौधों का रोपण जनप्रतिनिधियों यथा– मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 महापौर, अध्यक्ष नगरीय निकाय एवं सभी पार्षद, सभासद, मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं सभी सदस्य, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यगण तथा समस्त सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, एन॰सी॰सी॰, एन॰एस॰एस॰, नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, रोटरी, रोट्रैक्ट, लॉयन्स क्लब, इको क्लब, व्यापार मण्डल, किसान उत्पादक संगठन आदि अन्य सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, स्कूली बच्चों, रक्षा कर्मियों, मीडिया, ग्रामीणों आदि की सक्रिय भागीदारी से की गयी। सबके पयास से उत्तर प्रदेश पुनः हरित प्रदेश के रूप में विकसित होगा।

आजादी के गुम नाम सिपाहियों को नमन!

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज हैदराबाद, तेलंगाना में पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि

आजादी का अमृत काल चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र के भारतीय जनता पार्टी सरकार के उपलब्धियों से भरे हुए 8 सफल वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में संवैधानिक प्रमुख के रूप में पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के तौर पर 20 वर्ष पूरे किये हैं जो कि एक महान उपलब्धि है। मैं इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक, भाग्य नगर

देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले आजादी के सभी नाम–अनाम सिपाहियों से देश की वर्तमान पीढ़ी का परिचय कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं इस मंच से आजादी के गुमनाम सिपाहियों को नमन करता हूँ।

जिस लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से हमारे मनीषी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन संघ की स्थापना की थी कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं हो सकता, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति के बल पर वह सपना भी साकार हुआ और जम्मू–कश्मीर से सदा–सदा के लिए धारा 370 धाराशायी हुआ।

एकात्म मानववाद और अंत्योदय हमारी पार्टी की मूल अवधारणा रही है। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत को सरकार का मूल मंत्र बनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जन–जन के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं।

आजादी के बाद से लेकर अब तक आदिवासियों के सर्वसमावेशी कल्याण के लिए यदि किसी ने सबसे अधिक काम किया तो वे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं। आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अहर्निश कार्य किया है। हमारी पार्टी ने इस बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आज इस मंच से देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूँ कि वे दलगत भावना से ऊपर उठ कर आदरणीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करें।

कल ही जनता दल (सेक्युलर) और शिरोमणि अकाली दल ने माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपना समर्थन दिया है। मैं इस के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच. डी. देवगौड़ा जी और श्री सुखबीर बादल जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अन्य सभी दलों से भी अपील करता हूँ कि वे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करें।

उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनी। साथ ही, दूसरे स्थान पर रहने वाली समाजवादी पार्टी से

हमारा वोट भी लगभग 9% अधिक रहा। यूपी के 23 जिलों में हमने क्लीन स्वीप किया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 399 विधान सभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था जिसमें से 387 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 377 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 68 सीटों पर उसके उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। गोवा में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 35 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने भी गोवा विधान सभा चुनाव में 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था पर 21 सीटों पर उसकी जमानत भी जब्त हुई।

विधान सभा चुनावों के साथ–साथ देश में हुए लगभग सभी स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। लद्दाख से लेकर हैदराबाद तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, देश में हुए लगभग सभी निकाय चुनावों में भाजपा को शानदार जीत मिली है। गुजरात और असम में हम शत–प्रतिशत चुनाव जीते। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर में भी भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की।

हाल ही में संपन्न हुए विधान सभा उप–चुनावों में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश मूं हमने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की सीट सपा से छीन ली है। त्रिपुरा में चार विधान सभा सीटों पर संपन्न हुए उप–चुनाव में तीन पर भाजपा विजयी हुई है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति ख़त्म हुई है और विकासवाद, राजनीति का केंद्र बिंदु बना है। उनके नेतृत्व में देश की राजनैतिक कार्य संस्कृति भी बदली है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार प्रो–एक्टिव, प्रो–रिस्पोंसिव और प्रो–पुअर सरकार है जो जनसेवा के लिए सतत कटिबद्ध रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लोकतंत्र में पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस और विकासवाद के सिद्धांत को स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सौभाग्य योजना, जल–जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, जन–धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व वंदन योजना जैसे इनिशिएटिव ने भारत में कल्याणकारी शासन व्यवस्था की स्थापना की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक पिछले दो वर्षों से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार इस पर लगभग तीन लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है। अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना – इन तीन योजनाओं में लगभग 40 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवच दिया गया है।

आज भारत डिजिटल क्रांति को नया आयाम दे रहा है। आज दुनिया के डिजिटल ट्रांजेक्शन का 40% हिस्सा भारत से आता है। देश में इंटरनेट कनेक्शन में लगभग 231% का इजाफा हुआ है। अब तक लगभग 133 करोड़ आधार कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। पूरी दुनिया आज भी कोरोना के विपरीत प्रभाव से उबरने के लिए संघर्षरत है लेकिन भारत ने इस दौरान अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 8.4% से अधिक रही है जबकि दुनिया की औसत आर्थिक विकास दर महज 6% के आसपास है। विगत 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के बल पर भारत में गरीबी 22% से घट कर 10% के नीचे चली आई है। अत्यधिक गरीबी की दर भी कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट के बावजूद 1% से नीचे बनी हुई है। वैश्विक कोरोना महामारी के बाद भी भारत की विकास दर 2021–22 में 8.4% रही है जो विश्व में सर्वाधिक है। कोविड की परेशानियों के बावजूद जीएसटी संग्रह डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा। रिटेल ग्रोथ में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। भारी मात्रा में FDI भारत आया है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात भी किया है। 100 लाख करोड़ रुपये की पीएम गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचे की लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा और लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा। बड़े पैमाने पर क्रियान्वयित की गई इस परियोजना से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में वैक्सीन का निर्माण हुआ है और अब तक लगभग 197 करोड़ वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किये जा चुके हैं। हमने 1.48 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज मुफ्त में देशों को दी है। लगभग 100 देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराये हैं। हमारा वैक्सीन सस्ता और टिकाऊ है। हमारे वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की पूरी दुनिया में सराहना हुई है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति – दोनों पर काम हुआ। इसके लिए हजारों–लाखों सुझावों पर अध्ययन–मनन हुआ और मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्टीय स्वास्थ्य नीति – दोनों ही नीतियां भारत की मिट्टी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो भारत की जमीन और जड़ों से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा का भी ध्यान रखा गया है और संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये गए हैं।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं तो सुरक्षित हुई ही हैं, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढाँचे के विकास पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। कांग्रेस की सरकार में तो एक रक्षा मंत्री बोलते थे कि हम सीमा पर सड़क बनाएयंगे तो पड़ोसी देश नाराज हो जाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सही मायनों में स्वतंत्र विदेश नीति का सूत्रपात हुआ है।

एक समय दुनिया में हमारी छवि एक पिछलग्गू, पिछड़े और भ्रष्ट देश की थी जबकि आज पूरे विश्व में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। हाल ही में संपन्न G–7 देशों की बैठक में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। यह विश्व पटल में भारत की बढती साख और श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत को देखने के नजरिये में बदलाव की कहानी को रेखांकित करता है। विदेशों में रह रहे indian Diaspora को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुआयामी नेतृत्व के कारण एक आवाज मिली है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही विदेश नीति का परिणाम है कि हम युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने 23,000 छात्रों को सकुशल देश वापस लेकर आ सके।

जहां एक ओर भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, वहीं विपक्ष का व्यवहार अत्यंत ही गैर–जिम्मेदाराना रहा है। विपक्ष तर्क विहीन थोथी राजनीति कर देश की जनता को गुमराह कर रहा है। विपक्ष ने वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों पर जनता को गुमराह किया।

विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने लद्दाख और डोकलाम पर जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने राफेल पर जनता को गुमराह किया। देशहित के लिए जरूरी सुधारों अटकाना, लटकाना और भटकाना – यही विपक्ष का उद्देश्य रह गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विरोध करते–करते विपक्ष अब देश के विरोध पर उतारू हो गया है।

भाजपा शासित राज्यों में **'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'** के आधार पर विकास की राजनीति हो रही है, विपक्ष शाषित राज्य में तुष्टिकरण की घोर पराकाष्ठा की राजनीति हो रही है।

भाजपा शासित राज्यों में इस बात की प्रतिस्पर्द्धा है कि गरीबों के सबसे अधिक मकान किसने बनाए हैं, ग्राम विकास में कौन सबसे आगे है, सड़कें किसने अधिक बनाई है, गरीबों तक राशन किसने अधिक पहुंचाया है, मेडिकल कॉलेज किसने अधिक खोले हैं, सबसे अधिक वैक्सीन किसने लगाई है, सबसे अधिक शौचालय किसने बनाए हैं। जबकि, विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि तुष्टिकरण की राजनीति में कौन आगे है, गरीबों का राशन लूटने में कौन सबसे अधिक आगे है, भ्रष्टाचार में कौन सबसे आगे है और परिवारवाद की राजनीति में कौन सबसे आगे है।

कोविड के संक्रमण काल में जब सभी राजनीतिक दल लॉकडाउन की अवस्था में चले गए, क्वारंटाइन हो गए थे तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा ही संगठन मंत्र के आह्वान पर पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने आप को मानवता की सेवा में झोंक दिया। यह हमारे सामाजिक आयाम को रेखांकित करता है। पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू–कश्मीर में काफी कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं इन प्रदेशों में कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए समर्पित भाव से कार्य करने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ।

जिन–जिन राज्यों में हम अब तक सफल नहीं हो पाए, हमें वहां काम करना है और जनता का आशीर्वाद हासिल करना है। हर बूथ पर संगठन को मजबूत करना है। जिन राज्यों में हम सरकार में हैं, वहां भी जिन–जिन बूथों पर हम कमजोर हैं, वहां जम कर मेहनत करनी है। हमने ऐसे लगभग 50,000 बूथों को चिह्नित किया है जहाँ हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और संगठन को मजबूत बनाना है।

उत्तर–पूर्व के राज्य भीषण बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे हैं। मणिपुर में भू–स्खलन के कारण काफी नुकसान हुआ है। मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में त्वरित सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है। हमारी सरकारें भी लगातार राहत अभियान चला रही है। सरकार और संगठन मिल कर इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब हम भाजपा को वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 'Know BJP' अभियान शुरू किया है। अब तक मैं 40 से अधिक देशों के 'Head of Mission' के साथ संवाद कर चुका हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री जी, सिंगापुर के विदेश मंत्री और वियतनाम की सत्तारूढ़ पार्टी के तीसरे शीर्ष नेता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय आये और उन्होंने वहां काफी समय बिताते हुए भाजपा की कार्यसंस्कृति को समझा, यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दुनिया के बदलते दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

राजनीतिक प्रस्ताव

देशभर में भाजपा का बढ़ता जनसमर्थन

पूरे देश में भाजपा को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों में पुनः प्रतिबिंबित हुआ है। जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से चार राज्यों के चुनावों में भाजपा को न केवल विजयश्री प्राप्त हुई है, बल्कि शासन में रहे दल के पुनर्निर्वाचन का इतिहास भी बना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर एवं गोवा में पूर्ण बहुमत से पुनः भाजपा सरकारें निर्वाचित कर मतदाताओं ने राजनीतिक स्थिरता का संकेत दिया है। पंचायत से पार्लियामेंट तक, पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण तक, हर ओर भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत

गुजरात दंगों पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय से 'सत्यमेव जयते' का घोषवाक्य पुन: एक बार सत्य सिद्ध हुआ है। यह अब पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत गुजरात दंगों पर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बनाने के कुप्रयास हुए। इसमें कांग्रेसनीत विपक्ष के प्रतिशोध की राजनीति के अंतर्गत कुछ तथाकथित एनजीओ एवं बुद्धिजीवी और यहां तक कि विदेश से संचालित मीडिया का एक वर्ग एवं इनका पूरा 'इकोसिस्टम' तक शामिल थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठे आरोपों, निराधार आक्षेपों एवं कई प्रकार के दुष्प्रचारों को बरसों तक सहते हुए कभी भी भारतीय संविधान, न्याय प्रक्रिया एवं देश की न्यायिक व्यवस्था पर से अपना विश्वास नहीं डिगने दिया और अंतत: वे हर प्रकार की अग्निपरीक्षा से अक्षुण्ण होकर बाहर निकले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्षों तक जिस प्रकार राजनीतिक सहिष्णुता, सहनशीलता, परिपक्वता, उदारता तथा लोकतंत्र एवं संविधान के प्रति आस्था का प्रदर्शन किया है वह भारतीय समाज जीवन में एक उदाहरण है।

कांग्रेसनीत विपक्ष की नकारात्मक राजनीति

जो दल वर्षों सत्ता में रहा आज भारत के संविधान के तहत परिकल्पित रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहा है। अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल झूठ और फरेब की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। इन्हें न तो भारत के संविधान पर भरोसा है, न देश की जनता पर विश्वास है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों में इनकी आस्था है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति में आकंठ डूबे हुए हैं तथा सिद्धांतहीन, अवसरवादी एवं भ्रष्ट राजनीति का शिकार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर रचनात्मक कदम का विरोध कर, संसद से पारित कानूनों के रास्ते में रोड़ा अटकाकर तथा सड़कों पर भीड़तंत्र की राजनीति को बढ़ावा देकर वे देश के विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं। यही कारण है कि कांग्रेसनीत विपक्ष लगातार जनता का विश्वास खोता जा रहा है।

सशक्तीकरण और प्रतिनिधित्व: भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन

वर्ष 2017 में राष्ट्रपति पद के लिए श्री रामनाथ कोविंद का नामांकन और अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नामांकन से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भाजपा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी कमजोर एवं पिछड़े समुदायों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व एवं सशक्तीकरण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाजपानीत एनडीए गठबंधन ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद का प्रत्याशी बनाकर देश की समस्त महिला एवं जनजातीय समाज का सम्मान किया है तथा सर्वसमावेशी राजनीति के सिद्धांत को सुदृढ़ किया है।

सर्वसमावेशी शासन एवं गरीब कल्याण

हाल ही में देश भर में 'सामाजिक न्याय पखवाड़ा' मनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाज के गरीब से गरीब, शोषित, वंचित एवं उपेक्षित वर्गों की सेवा के प्रति अपने संकल्प को और भी अधिक सुदृढ़ किया है। भाजपा शुरू से ही 'अंत्योदय' के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रही है और इस बात में इसका अटूट विश्वास है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के बिना देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। वंचित एवं उपेक्षित वर्गों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। महिला, युवा, अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के नए अवसर मिल रहे हैं और हर व्यक्ति के लिए स्वाभिमान एवं न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। भाजपा ने न केवल सेवा के संकल्प को और भी अधिक सुदृढ़ किया, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न स्तरों पर भागीदारी की।

'नए भारत' का संकल्प

पिछले 8 वर्षों में भारत ने न केवल लंबे समय से चली आ रही विभिन्न समस्याओं को निर्णायक रूप से हल किया है, बल्कि 21वीं सदी में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक ऐतिहासिक सुधार भी किए हैं। कांग्रेसनीत यूपीए के कुशासन, भ्रष्टाचार, घपलों एवं घोटालों को देश आज भी भूला नहीं है। एक दिशाहीन एवं नेतृत्वविहीन सरकार केंद्र में थी। पूरे देश में निराशा एवं हताशा का वातावरण था। ऐसे समय में पूरे देश ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट जनादेश दिया। आज, आठ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश में एक नई कार्य-संस्कृति का शुभारंभ हुआ है जिसके कारण भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन आज जन-जन को प्राप्त हो रहा है।

पूरा पढ़ें: bit.ly/PoliticalResolutionBJPNE

100 दिनों में 10 बड़े फैसले नये उत्तर प्रदेश का निर्माण

अरुण कान्त त्रिपाठी

विधानसभा चुनाव 2022 में शानदार सफलता प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे फार्म के साथ कार्य आरंभ किया। यह ऐसा समय रहा जब उत्तर प्रदेश विधानपरिषद कांग्रेस से मुकत हो गई। विधानपरिषद चुनाव में बीजेपी ने 33 सीट पर जीत हासिल की। भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत प्राप्त करके विपक्ष पर भारी बढ़त बना ली।

सरकार ने बूस्टर डोज देते हुये योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में पार्टी की ओर से यूपी चुनाव 2022 को लेकर जारी किए गए संकल्प पत्र के 97 प्वाइंट्स को बजटीय प्रावधान के दायरे में लाया गया। कानून व्यवस्था को लेकर बनी छवि को सरकार बरकरार रखने में कामयाब रही। दंगों और अन्य मामलों पर रोक के लिए भी कड़े कदम उठाए गये। नियुक्तियों की प्रक्रिया को शुरू कराई गई। हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी के दायरे में लाने की योजना के लिए सर्वे शुरू कराया गया। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार के सीधे जुड़ने को लेकर तमाम मंत्रियों को क्षेत्र में जाकर रहने और वहां पर बात करने का जिम्मा सौंपा। मंत्रियों के बीच जिलों का वितरण किया गया। इससे सरकार जनता के द्वार अभियान सफल रहा, क्योंकि 18 मंत्रियों ने हर कमिश्नरेट में 72 घंटे तक शिविर लगाया। जनता चौपाल का आयोजन किया, विकास कार्यों का आकलन किया, ब्लॉकों, गांवों में गए इससे अभियान शुरू होने से लोगों को अपनी समस्या रखने का एक मंच मिला।

योगी सरकार - 2.0

चुनाव के बाद सरकार ने 100 दिन के लिए 130 संकल्प लिए थे। उसमें से 97 संकल्प पूरे हो गए हैं।130 संकल्पों में से 97 संकल्प को पहले बजट में शामिल किया गया था। 100 दिन में निवेश की 80 हजार से अधिक परियोजना का शिलान्यास हुआ। 1400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कवर हुए। सरकार के प्रयासों से यूपी अब डाटा सेंटर बनने का हब बन रहा है। इसके लिये 4 नए सेंटर के जरिए 4000 युवकों को रोजगार दिया गया। प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई, निवेश से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर दिए। 10 हजार सरकारी नौकरी दी, 90 लाख रोजगार के लिए 16000 करोड़ के लोन दिए गए।

नियुक्तियों पर जोर रहा

सरकार बनते ही पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन ने मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग में नियुक्तियों को तेज किया गया। यूपीपीएससी की ओर से पिछले 100 दिनों में 3800 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें से 3500 से अधिक को नौकरी मिली है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 20 हजार पदों पर अगले 6 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाए जाने का भी निर्णय सरकार

ने लिया है।

कौन से काम पूरे हुए

- नगर निकायों में 280 पिंक टायलेट का निर्माण पूरा हो गया।
- अमृत योजना के तहत पेयजल की 19 परियोजनाएं हुई।
- सभी 12022 वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू हुआ।
- स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 50 परियोजनाओं का काम तय समय अनुसार पूरा हुआ।
- स्मार्ट सिटी में निर्माणाधीन 75 परियोजनाओं का काम पूरा हुआ।
- पीएम स्वनिधि योजना में 84148 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरण
- 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है।

निवेश और रोजगार पर जोर

भाजपा सरकार चुनाव के दौरान युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के दावे के साथ सत्ता में पहुंची है। इस दावे को पूरा करने के लिए पिछले दिनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर को प्रदेश में एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का संदेश देने की कोशिश हुई। उद्योगों को बढ़ाकर सरकार बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की रणनीति तैयार कर रही है।

दंगाइयों पर एक्शन

एक राजनीतिक डिबेट को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश माहौल खराब करने की कोशिश की गई। 3 जून को कानपुर में बवाल हुआ। वहीं, 10 जून को दंगाइयों ने प्रयागराज में बवाल किया। कानपुर दंगे के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी और प्रयागराज के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में सैकड़ों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई की गई है। वहीं, हयाज जफर के करीबी के घर को भी नोटिस गया है। इन ऐक्शन के बाद बलवाइयों को शांत करने में कामयाबी मिली है। पहली बार बकरीद पर प्रदेश का माहौल अच्छा रहा है।

लाउडस्पीकर पर बड़ा फैसला

देश में मचे लाउडस्पीकर विवाद के बीचयोगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज को परिसर तक ही सीमित करने का आदेश जारी किया गया। इस अभियान में पुलिस को भी लगाया तो तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने लगे। प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाए जाने की कारवाई हुई। कार्रवाई को लेकर किसी प्रकार का तनाव नहीं हुआ और इसकी तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया।

अवैध स्टैंडों पर कसा गया शिकंजा

अवैध ऑटो स्टैंडों को लेकर अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया गया। अवैध स्टैंडों को खत्म कर स्टैंडों को नियमित करने का निर्देश दिया गया है। स्टैंडों के ठेकों में दागदार को किसी भी स्थिति में शामिल नहीं कराया जाएगा। स्टैंड में होने वाले अपराधों को रोकने में इससे मदद मिलेगी। इस आदेश को लागू करने की कार्रवाई चल रही है।

सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई

सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनहित की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करके सरकार ने इसका संदेश दे दिया। डीएम औरैया को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही पहले महीने में ही दो सौ करोड़ से ज्यादा की अवैध सम्पत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। इसमें 25 माफिया डीजीपी दफ्तर और आठ शासन की ओर से चिन्हित किए गए थे।

पेपर लीक पर सख्ती

परीक्षाओं में पेपर लीक पर अब सरकार की ओर से सख्ती दिखाई जाने लगी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड और गिरफ्तार कर लिया। कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमाम बोर्ड और परीक्षा समितियों को पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

अपराधियों पर एक्शन

दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 30 दिनों में ही 100 से अधिक अपराधियों और माफियाओं की सम्पत्ति पर सरकार ने जब्त किया है। प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वॉड को दोबारा शुरू कर दिया गया है। पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री आवास पर एक बार फिर जनता दर्शन की शुरुआत कराई गई है। इसमें हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी होती है।

राशन योजना को बढ़ाया

कोरोना काल में सरकार की ओर दी जाने वाली मुफ्त राशन योजना को योगी सरकार ने तीन माह के लिए बढ़ाया। सरकार बनते ही कैबिनेट बैठक में 15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजना का रिटर्न गिफ्ट दिया गया। सरकार राज्य में गरीबों के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना को संभवत: अगले तीन महीने के लिये बढ़ा भी सकती हैं।

कानून व्यवस्था पुख्ता

दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाने पर जोर दिया गया। एसडीएम, सीओ और तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में नागरिकों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए रात में तैनाती स्थल पर ही रहें। उत्तर प्रदेश में महिला होमगाड्र्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल की ट्रेनिंग देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। यूपी में होमगार्डों के 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। इसकी भी प्रक्रिया शुरू की गई है।

काम जो पूरे होने हैं

सिटी बस सेवा के लिए एप विकसित करने का काम अधूरा रह गया है.

14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुना करने का काम अधूरा रह गया है.

सही अर्थों में भाजपा को दूसरा कार्यकाल जनता ने पिछले पाचं साल विश्वास के साथ विकास करने के लियेदिया है, इसमें हम एक नई उड़ान के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर की बनाने का देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, स्वभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार ने 10 सेक्टर चुनकर व्यवस्थित कार्य योजना बनाया है। जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमने अगले पांच वर्ष की, जो कार्य योजना तैयार की है। इसमें सौ दिन के लक्ष्य जो तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवावारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखती थी, लेकिन हमने पांच साल में कानून व्यवस्था की बेहतर किया। उत्तर प्रदेश के बारे में

आम जनमानस के मन में विश्वास पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदलीं।

नए ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण का लक्ष्य

100 दिन के लक्ष्य में 500 नए ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण शामिल था। इसके सापेक्ष 503 सड़कों का निर्माण किया गया। इसी तरह से 500 किमी मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 511 किमी मार्गों को सुधारा जा चुका है। 60 अंतरराज्यीय स्वागत द्वारों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया गया था, जिसके सापेक्ष 59 पर काम हो पाया। इस अवधि में 10 हजार किमी. सड़कें गड्ढा मुक्त करनी थीं और 10,380 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया गया है। नवीनीकरण का लक्ष्य नहीं लिया गया था, पर 2,910 किमी सड़कों का नवीनीकरण भी कर दिया गया है।

प्राकृतिक खेती कराने की कवायद

कृषि विभाग ने सौ दिन के लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 45.50 करोड़ से ज्यादा की रकम का वितरण किया गया। हालांकि एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) बनाने और प्राकृतिक खेती शुरू कराने की कवायद पूर नहीं हो सकी है। लेकिन विभाग तेजी से लक्ष्यों को पूरा कराने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.58 करोड़ किसानों को राशि वितरित की जा चुकी है। कुसुम योजना के तहत 10000 किसानों को लाभ दिया गया है।

11.33 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट

सरकार के पहले सौ दिन के कार्यकाल में 11.33 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य पूरा किया है। सरकार 1.0 ने डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम के 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। विधानसभा चुनाव से पहले तक 9 लाख विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति की गई थी। और फिर योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद 11.33 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा था।

किसानों को डेढ़गुना ज्यादा भुगतान

गन्ना विभाग ने सौ दिन में गन्ना किसानों को 8000 करोड़ रुपये के भुगतान का लक्ष्य रखा था। इसके सापेक्ष डेढ़ गुना ज्यादा 12500 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया। विभाग ने 15 हजार किसानों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी पूरा किया है। इसके अलावा 46 लाख से ज्यादा किसानों के गन्ने का डिजिटल सर्वेक्षण, सभी किसानों को यूनिक ग्रोअर कोड जारी करने, नैनो यूरिया का एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव कराने का लक्ष्य पूरा किया गया। सहकारी गन्ना विकास समितियों के 5 लाख अंशधारक किसानों को शेयर प्रमाणपत्रों का वितरण अभी किया जा रहा है।

भाजपा सरकार में आस्था को मिल रहा पूर्ण सम्मान

भारत का संकल्प आत्म निर्भर भारत : नरेन्द्र

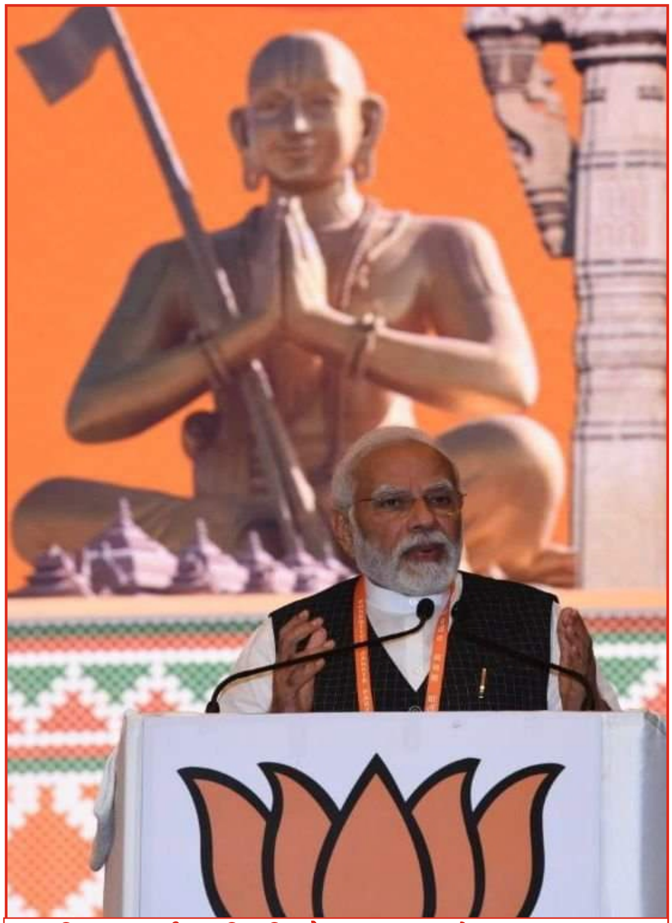

राष्ट्रीय कार्यकारीणी बैठक समारोप, भाग्यनगर

देश के यशस्वी और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से आजादी के अमृत काल में देश को विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया।

मोदी जी ने कहा कि :

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब देश अमृतकाल में अपने लिए नए संकल्प ले रहा है। जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, तब देश जिस ऊंचाई पर होगा, उसके लिए प्रयत्न करने का यही सही समय है। एक राजनीतिक दल के रूप में, भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो अगले 25 वर्षों के लिए अपना एक रोडमैप बनाए तथा भविष्य से जुड़ी नीतियों और निर्णयों पर मंथन करे।

विपक्षी पार्टियों की स्थिति बहुत खराब है। हमें उनकी इस स्थिति से सीख लेनी है कि वो कौन सी बुराई और कमियाँ हैं, जिसके कारण वे इतने नीचे आ गए, जनता से दूर होते गए और लगातार दूर होते ही जा रहे हैं। हमें उन चीजों से अपने आप को बचाए हुए रखना है क्योंकि हम अपने के लिए नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं।

सत्ता से बाहर होने पर कई पार्टियों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है जबकि भाजपा जिन राज्यों में दशकों तक सत्ता में नहीं थी, वहां भी पार्टी का कैडर रहा, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। हमारे कार्यकर्ता न थके हैं, न झुके हैं और न रुके हैं। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा के कार्यकर्ता देश के लिए अविचल रह कर काम कर रहे हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है।

आठ साल पहले देश में निराशा, नकारात्मकता, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था लेकिन जब देश की जनता ने भाजपा में अपना विश्वास जताते हुए भाजपा की सरकार बनाई तो उसके बाद से देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हमने जनता के भरोसे को टूटने नहीं दिया।

आज हमारी सरकार की पहचान है – P2G2 अर्थात् Pro-People, Pro-Active Good Governance. जब दुनिया कोरोना के सामने किंकर्तव्यविमूढ़ की सी स्थिति में थी, तब हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे थे। एक समय की निराशा आज आशा, विश्वास, भरोसा और श्रद्धा में बदल चुकी है। आज देश अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से निरंतरता की ओर बढ़ रहा है। आज का भारत तुष्टिकरण के कालखंड से आगे बढ़ कर तृप्तिकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पहले गरीबों को बुनियादी सुविधाओं और आगे बढ़ने के अवसरों के बिना जिस तरह की जिंदगी बितानी पड़ी, उनके बच्चों को उन हालातों से गुजरना नहीं पड़ेगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है– हमें आने वाली पीढ़ियों को आज से बेहतर भविष्य देना है, आज से बेहतर जीवन देना है।

दशकों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी भी क्यों देश की प्रगति की कोई दिशा तय नहीं कर पाई? आज देश की प्रगति की दिशा भी तय है, संकल्प, सपने भी साथ है। हमारी नीति और नीयत भी समान हैं। आज भारत का संकल्प आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और गरीब कल्याण का है। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। आज का भारत बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पर चल रहा है। प्रगति की यही दिशा देश को विश्वगुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करेगी।

युग बदलता है, समय बदलता है, देश बनते हैं, देश कभी रुकता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी भूगोल और इतिहास भी बदलते हैं लेकिन हमारा देश शास्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहने वाला है।

जब कोरोना के कारण दुनिया भर में गरीबी बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, तब उस कालखंड में भारत में गरीबी में कमी आई है। यह हमारी नीति और नीयत का परिचायक है। जब पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित कोरोना के कारण प्रभावित

हो रही थीं तब हमारा भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित है, तब भारत निर्यात में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। जब दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन अभी भी एक बड़ी चुनौती है, तब भारत 200 करोड़ वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर करने की कगार पर खड़ा है। हमने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ 23 करोड़ डोज दुनिया के गरीब देशों को पहुंचाए हैं और वहां गरीबों की जिंदगी बचाई है। भारत वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने और उसके समाधान की दिशा में काम कर रहा है।

> 'युग बदलता है, समय बदलता है, देश बनते हैं, देश कभी रुकता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी भूगोल और इतिहास भी बदलते हैं लेकिन हमारा देश शास्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहने वाला है'।

आज भारत परिवारवाद की राजनीति और पुरानी मानसिकता से ऊब चुका है। आने वाले दिनों में परिवारवाद की राजनीति करने वाले ऐसे दलों के लिए टिक पाना मुश्किल है। हिन्दुस्तान की जनता अब ऐसी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगी। स्थापना काल से ही हमारी पार्टी की आत्मा में जतनम कमउवबतंबल का संस्कार रहा है। सरदार पटेल ने 'एक भारत' का निर्माण किया। वे कांग्रेस पार्टी के नेता थे लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य हमें मिला।

देश के सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाने का साहस भी हम ही कर सकते हैं। देश में जो कुछ उत्तम है, सब हमारे ही हैं – हम इस भावना से काम कर रहे हैं।

> 'आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज की महिला भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाली हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद पहली बार आदिवासी समाज को नई पहचान मिल रही है। पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्र के सर्वोच्च प्रदेश पर आसीन होने का सपना साकार हो रहा है।'

जो वर्षों तक देश की सत्ता पर काबिज रहे, वे देश हित की योजनाओं का भी अंधा विरोध करने पर उतारू हैं। जनता उन्हें न तो सुनती है, न स्वीकारती है, बस नकारती है। नकारात्मकता के बीच सकारात्मक बात को उठाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। हमने गाँव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किये, उन्हें जनता तक पहुंचाना जरूरी है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो प्रयास किये, उसे जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।

मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सात सूत्र बहुत जरूरी हैं। ये सूत्र हैं – सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। ये सात सूत्र हमारे जीवन से जुड़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाने में सफल होंगे।

> 'मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सात सूत्र बहुत जरूरी हैं। ये सूत्र हैं - सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। ये सात सूत्र हमारे जीवन से जुड़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाने में सफल होंगे।'

भाजपा ने सभी कार्यक्रमों में बहनों को विशेष अवसर दिया है। इस बार की कार्यकारिणी बैठक में मंच संचालन से लेकर प्रस्ताव पेश करने तक में बहनों को भूमिका दी गई है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। इस तरह से कार्यक्रमों की रचना लगातार होनी चाहिए।

आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज की महिला भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाली हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद पहली बार आदिवासी समाज को नई पहचान मिल रही है। पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्र के सर्वोच्च प्रदेश पर आसीन होने का सपना साकार हो रहा है।

'सबका प्रयास' हमारी हर चीज में होना चाहिए। हमारी विचारधारा और कार्यक्रम एक ही है – नेशन फर्स्ट। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जनता ने हमें स्वीकार किया है, आशीर्वाद दिया है लेकिन अभी भी कुछ टोलियाँ ऐसी बैठी हुई हैं जो सत्य को आगे पहुँचने में रुकावटें डालती हैं लेकिन हमें सर्वस्पर्शी एवं सर्व समावेशी विकास और गरीब कल्याण के काम पर ही आगे बढ़ना है।

आजादी का अमृत महोत्सव सरकार का, भाजपा का या नरेन्द्र मोदी का कार्यक्रम नहीं है, यह पूरे देश का कार्यक्रम है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के इतर किसी और पार्टी की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में कोई भूमिका नहीं है। यह राजनीतिक असहिष्णुता का परिचायक है।

हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करते हुए चलना है। भाजपा के विस्तार का मतलब है– एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार! भाजपा के विस्तार का मतलब है– राष्ट्र प्रथम के संकल्प का विस्तार! हमें थ्पतेज ज्पउम टवजमते को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी धरती से हमें 'एक भारत' दिया था। आज हम उसी धरती से 'एक भारत को श्रेष्ठ भारत' बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी पूरी टीम को और तेलंगाना प्रदेश भाजपा इकाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

आजादी के अमृत काल में हम हर जिले में 75 तालाब बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। 25 वर्ष का अमृतकाल देश के उज्जवल भविष्य के साथ भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आयेगा। हम एक नए भारत का सपना साकार करने के लिए आगे बढ़ें, यही संकल्प होना चाहिए। हमारा सपना हिंदुस्तान को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का है, जन–कल्याण का है। हम सब एक नए भारत के निर्माण का सपना जरूर पूरा करेंगे।

विद्या अमृतम् अनुश्ते

सर्वेंटक्लास बनाने वाली शिक्षा पद्धति बदले

सर्व विद्या की राजधानी काशी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के दो वर्षों बाद देश भर के शिक्षा विद, शिक्षा नीति निर्माणकर्ताओं का अखिल भारतीय समागम हुआ। जिसमें बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार, शिक्षा को संकुचित सोच के दायरों से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन, दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें। हमारे यहाँ शिक्षा में अलग–अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था, क्योंकि यहाँ अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे। बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था, क्योंकि यहाँ ज्ञान और शिक्षा, बहु आयामी Multi Sectoral थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणास्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध करायें, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, छात्र–छात्राओं को देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविष्य को भी उतना ही ज्यादा लाभ होगा।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम काशी

नए भारत के निर्माण के लिए, नई व्यवस्थाओं का निर्माण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है। जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्ष्यों को पाने की देश कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत में हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उबरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में एक हैं। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में, जहाँ पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है, पूरा अंतरिक्ष उनके बहुत पास में आ रहा है दोस्तों। देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए भी जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

जब देश का मिजाज़ ऐसा हो, जब देश की रफ़्तार ऐसी हो तो हमें अपने युवाओं को भी खुली उड़ान के लिए नई ऊर्जा से भरना होगा। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आये थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है। और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझें, उसकी आकांक्षाओं को समझें, तभी तो खाद पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है दोस्तो। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, हमें वैसा ही शिक्षण, वैसी ही संस्थानों की व्यवस्थाएं, वैसा ही Human Resource Development का हमारा मिजाज, अपने आपको सज्ज करना ही होगा। नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें skilled बनाने पर है। हमारे युवा skilled हों, confident हों, practical हो, calculative हो, शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है।

देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच शिक्षा व्यवस्था और इससे जुड़े आप सभी महानुभावों की भूमिका कितनी अहम है, इसका एक उदाहरण मैं अपने गुजरात के मुख्यमंत्री काल के

शुरुआत के कालखंड का एक अनुभव बताता हूं। मैं नया–नया मुख्यमंत्री बना था, सरकार वरकार की दुनिया से मेरा कोई नाता ही नहीं था मैं बहुत दूर था, अचानक काम आया था। तो मैंने एक कार्यक्रम मनाया था। मेरे सभी सचिवों को मैंने कहा कि आप ही आपके डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री हैं और मुझे बताईये पांच साल में आप अपने डिपार्टमेंट को कहां ले जाओगे? कैसे ले जाओगे? अचीव क्या करोगे? उससे गुजरात के सामान्य मानवीय के जीवन को क्या लाभ होगा? उसका एक अपना विजन और पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए। ये मैंने सभी विभागों के सचिवों को कहा और हर दिन शाम को पांच बजे सभी मेरी मंत्रिपरिषद के मंत्री और सभी सचिव हम बैठते थे और एक सचिव आकर के अपने विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन देते थे, फिर डिबेट होती थी। सभी सचिव जो पहले भी कोई एग्रीकल्चर सचिव रहा होगा, वो भी वहां बैठा हुआ है। सब लोग अपने अपने विचार रखते थे। डिबेट होती थी, हमारे मंत्री भी डिबेट करते थे। मैं सुनता रहता था। सीखने का प्रयास करता था। एक दिन और ये कार्यक्रम मेरा करीब महीने भर चला था और शाम के 5 बजे शुरू होता था, रात 10 बजे तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाजत मिलती थी और बड़ी ही, बड़ा ही पदजमदेम वो कार्यक्रम चला और शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो मेरे यहां उद्योग के जगत के संबंधित प्रेजेंटेशन हुआ। आने वाले दिनों में वो औद्योगिक क्या–क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में औद्योगिक विकास कैसा होगा, सारा बता रहे थे। तो सारा कार्यक्रम पूरा होते ही शिक्षा सचिव मेरे पास आए। क्योंकि दूसरे दिन शिक्षा सचिव का कार्यक्रम था। उसने कहा साहब मैं कल नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्या बात करते हो भई? एक महीने पहले आपको तैयारी करने के लिए कहा और आप last moment कह रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा तैयार तो है, मैं कर सकता हूं, लेकिन आज जो मैंने औद्योगिक विकास का जो प्रेजेंटेशन देखा उसको देखकर के मुझे लगता है कि हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है। हम बाएं जा रहे हैं, वो दायें जा रहे हैं। तो मैं इसकी लाईट में मेरी जो प्रेजेंटेशन है, उसको modify करने के लिए मुझे समय चाहिए, तब जाकर के हम एक inclusive growth की दिशा में साथ मिलकर के शिक्षा और industry चल सकते हैं। हमें भी अब तो पूरी दुनिया का पता होना चाहिए, हर university के बारे के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है। उसमें हमारा देश कहां है। उसमें हमारे युवा कहां हैं। आने वाले 15–20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होगा, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं। ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं? मैं आज दिन बिता रहा हूं, एग्जाम दे रहा हूं। convocation कर रहा हूं, क्या यही मेरा मैं जिस पद पर हूं, वही काम है, क्या मेरा काम ये है कि मैं ऐसा संस्थान खड़ा करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल, कॉलेज में आएगा, आजादी के जब 100 साल होंगे, जब वह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा तब मेरा देश वहां पहुंचेगा, मैं वो व्यवस्था आज पैदा करके जाऊंगा। आप सबको वर्तमान संभालना है, आपके पहले जो करके गये हैं, उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं, उनको future के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं future के लिए विकसित करनी होगी। क्योंकि, आज बच्चों की जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं जिनके उत्तर अभी मैंने कहा जिन बच्चों को मिलके आया हूं। आपको भी घर में पता चलता होगा छोटे–छोटे आपके पोते–पोती भी आपको सवाल पूछते होंगे, आपके नन्हें मुन्हें बेटे आपको सवाल पूछते होंगे, आपको सोचना पड़ता होगा अरे भई ये कहां सर खा रहा है। वो सर नहीं खा रहा है आपका सर उसको जवाब नहीं दे पा रहा है दोस्तो, वो सब है। आपके हर किसी के घर में ये अनुभव आया होगा जी, आज की पीढ़ी जिन बातों को लेकर के आती है। वो तो गूगल पर 10 चीजें सवाल पूछते हैं, बोलते हैं आप क्या कर रहे हो गूगल तो ये कह रहा है। आपको counter करता है बच्चा। अब ये बच्चे आपकी university में दस साल के बाद आएंगे तब क्या हाल होगा आपका? हमें अभी से तैयार करना होगा अपने–आप को। आप घर में भी अपने बच्चों के साथ mismatch अनुभव कर रहे हैं। जब स्कूल, कॉलेज के कैंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी होगी। इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी। और हम वहां उसके योग्य नहीं होंगे तो उनके साथ कितना बड़ा गहरा अन्याय हो जाएगा दोस्तों, और इसलिए आवश्यक है कि हम भाविष्य को जाने, समझें व्यवस्थाओं को विकसित करें। मैं अभी कुछ दिन पहले Digital India अभियान के तहत गांधीनगर में एक exhibition देखने गया था। वहां सरकारी स्कूल के बच्चें थे। बारहवीं, दसवीं eleventh के बच्चें थे। वहां बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स तैयार किये थे, जो पकमें रखे थे, मैं बहुत उसको समझने की, देखने का प्रयास कर रहा था और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम। रिसर्च का ऐसा पोटेंशियल, कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वाली बातें सुनकर मैं दंग रह गया। वहां कई बच्चे बायोटेक और जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। उनकी क्लास में जब साइंस के फंडामेंटल्स पढाये जा रहे हैं, तब वो जीन मैपिंग, Affinity chromatography (एफिनिटी क्रो–मेटोग्राफी) और जेनेटिक लाइब्रेरी बेस्ड टूल्स की बात कर रहे थे। अब कितना बड़ा अंतर है आप कल्पना करिए। मैं उनके

हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते। परिणाम के साथ प्रमाण भी होना चाहिए।

काम को देखकर सोच रहा था कि जब ये हायर एजुकेशन में पहुंचेगे, तो हमारे institutes इनकी आधुनिक सोच के मुताबिक तैयार होंगे क्या? अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन में पहुँचने का इंतजार करेंगे तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी दोस्तो। इसलिए, हमें ये अभी सोचना होगा कि जिस उम्र में भी बच्चों के मन में मोटिवेशन है, उसी उम्र में उन्हें गाइडेंस और रिसोर्सेस मिलें, इसका प्रबंध हमने सोचना पड़ेगा। हमें अपने संस्थान में ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम करना चाहिए।

इसी महीने के आखिर में, 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दो साल पूरे होने वाले हैं। और अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि बड़े मंथन के बाद ये शिक्षा नीति बनाई। कस्तूरीरंगन जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, उसके कारण ये संभव हुआ। और इतना विविधता भरा देश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस प्रकार से स्वागत हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है जी। बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन इसकी विशेषता देखिए, इसको बनाने में तो मंथन हुआ, आमतौर पर सरकार का स्वभाव होता है एक document बन जाता है और document समय के भरोसे छोड़ दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। आपके भी टेबल पर कुछ दिन शोभा बढ़ाता है document। फिर वो भी टेबल पे से हट जाता है कोई नया document आता है वो जगह ले लेता है। बात वहीं समाप्त हो जाती है। इसका अनुभव आपको भी है, यहां बैठे लोगो को भी है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने हर पल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिंदा रखा है। मैं स्वयं भी इतने कम समय में कम से कम 25 सेमिनार में गया हूं शायद। 25 से ज्यादा, और इसी विषय पर मैं बोलता रहा हूं। ये रिपोर्ट देने के बाद स्वयं कस्तूरीरंगन जी लगातार संवाद कर रहे हैं, हर क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहें हैं। उनके clarification चाहिए समझा रहे हैं, उनके पीछे का vision क्या है background information वो समझा रहे हैं। पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये क्योंकि 30 साल के बाद आया document सिर्फ कागज का दर्रा हमारे पास पहुंच जाने होगा नहीं जी। आप भी यहां जब तीन दिन मंथन करोगे उसकी कई बारिकियां हैं जो शायद अपने पूरा पन्ना–पन्ना पढ़ लिया होगा लेकिन अब नए तरीके से आपके सामने उजागर होगी। इसलिए अपनी university के अंदर भी ऐसे ही निरंतर मंथन की योजना बनाकर के यहां से जाना है। सिर्फ यहां से आप सुनकर के मत चले जाना। आपके साथ जुड़े हुए जो बाकी साथी हैं। वे भी ऐसा ही मंथन करें, उसमें से और मंथन निकाले जी तब जाकर के इसका लाभ होगा। और इसके Implementation के लिए जो चुनौतियां हैं। उसकी हर बारीकि पर हमें गौर करते रहना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोंच के दायरों से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हम केवल डिग्रीधारक युवा तैयार न करें, बिल्कि देश को आगे बढाने के लिए जितने भी मानव संसाधन की जरूरत पड़े, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को दे।

आज जब कोई काम अपने हाथों में लेता है, तो समस्यायों का समाधान भी तेजी से निकलता है। समस्या समझकर के यार मैं कहां पड़ूं, इसमें तो समाधान कभी नहीं निकलता है। साथियों, इन दो सालों में देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई ठोस कदम उठा चुका है। इस दौरान, Access, Quality और Future Readiness जैसे जरूरी विषयों पर हुई वर्कशॉप्स ने भी बहुत मदद की है। देश विदेश के academicians इनसे से जो चर्चाएँ हुईं, मेरा भी देश के शिक्षामंत्रियों के साथ, शिक्षाविदों के साथ जो संवाद हुआ, उसने भी इसकी गति को आगे बढ़ाया है और अभी कुद दिन पहले हमारे धर्मेंद्र जी ने देशभर के शिक्षा मंत्रियों को भी बुलाया है। जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ भी की थी। लगातार कोशिश हो रही है कि इन चीजों को हम शत–प्रतिशत साकार कैसे करें पाएं ? राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। और आज सभी के प्रयासों का परिणाम है कि देश, और खासकर देश का युवा इस बड़े बदलाव में भागीदार बन रहा है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर overhaul पर भी काम हुआ है। आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए IIT और IIM की स्थापना हो रही है। 2014 के बाद से, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में समान स्टैंडर्ड्स के लिए इस वर्ष से Common University Entrance Test (CUET) भी लागू किया गया है। ऐसे ही कई और भी Reforms किये गए हैं। देश के इन प्रयासों का परिणाम है कि World University Rankings में भारतीय संस्थानों की संख्या में धीरे–धीरे संख्या में वृद्धि हो रही है। ये बदलाव केवल शुरुआत है। अभी हमें इस दिशा में लम्बी दूरी तय करनी है।

मुझे ये भी संतोष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में, संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओँ को भी आगे बढाया जा रहा है। मैं यहाँ देख

रहा हूँ कि, इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी।

मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार करना होगा। इस दिशा में देश लगातार प्रयास भी कर रहा है। हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। करीब 180 उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए विशेष कार्यालय की स्थापना भी की गयी है। मैं चाहूँगा कि आप सभी इसी दिशा में न केवल जरूरी विमर्श करें, बल्कि भारत के बाहर की व्यवस्थाओं से भी परिचित होने का प्रयास करें। ये नई व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से भी जोड़ने में मदद करेंगी।

इन तीन दिनों में आप लोग अलग अलग sessions में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी इस चर्चा से देश के लिए अलग–अलग क्षेत्रों में नए रास्ते खुलें, युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन हो। दुनिया के कई देशों ने अलग–अलग क्षेत्रों में जो रफ़्तार पकड़ी है, उसमें एक बड़ा योगदान वहाँ की यूनिवर्सिटीज का भी है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के युवाओं की इनोवेटिव सोच और नए आइडियाज से नई व्यवस्थाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। इससे फ्रेश टैलेंट आता है, फ्रेश पकमें आते हैंद्य मैं चाहूँगा कि इसे लेकर भी आप सब चर्चा करें, कोई रोडमैप तैयार करें। यूनिवर्सिटीज कैसे सरकार के साथ अलग–अलग क्षेत्रों में पार्टनरशिप कर सकती हैं, इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अपनी एक्सपर्टीज आपको ही तय करनी है। आप जिस क्षेत्र में हैं, उसे लेकर सर्वे और स्टडी करें, सरकार को सुझाव दें। आपकी university का जो 50–100 किलोमीटर को जो दायरा होगा, वहां की जन सामान्य की समस्याएं क्या हैं? उसका उपाय क्या है? Resources क्या हैं? उस Resources के लिए क्या किया जा सकता है? वहां के सामान्य व्यक्तियों की वृत्ति प्रवत्ति क्या है? आपके स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। स्थानीय रूप से बढ़िया रिपोर्ट बनेगी, सरकार की कोई योजना चलती है तो उसकी अच्छाईयां क्या है, कमियां क्या हैं, सुधार की संभावना क्या हैं, बढ़िया रिपोर्ट बन सकता है। ये सारी बाते सरकार के अंदर गंभीरता से अगर लिया जाए बहुत बड़ा परिणाम आता है। मुझे याद है मैं गुजरात में था तो एक बार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लोगों ने Rural Development में काफी रिसर्च करके कुछ किताबें तैयार की थी। उस दिन उन्होंने मुझे गिफ्ट की। मैंने जरा बड़ी बारीकि से उसे देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। मैंने डिपार्टमेंट को काम दिया। मैंने कहा कि भई ये जो स्टूडेंट्स ने काम किया है। आप जरा देखिए सरकार जहां जा रही है और ये बच्चें जो कह रहे हैं, कितना अंतर है और आप हैरान हो जाएंगे उसमें से बहुत सी चीजें मुझे Rural Development के मेरे काम में इतने मदद आयी। विद्यार्थियों ने टीचर्स का किया हुआ काम था। जो सरकार में Air Condition कमरे में बैठकर के निर्णय करना मुश्किल होता है जी। जो फील्ड में हमारी ये पीढ़ी जाती है बहुत अच्छा उसका अर्क निकालकर के ले आती है और कुछ चीजों का कल्पना भर का लाभ हुआ हो ये भी ध्यान में आता है, और मुझे विश्वास है। अब जैसे हमारे यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लैब में जो करती है। कितना ही अच्छा काम करे, लेकिन उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाये, international magazine में उसका आर्टिकल भी छप जाये। उसको डिग्री भी मिल जाये, लेकिन वो तो मामला लैब में ही रह जाएगा। हमारे पास लैब टू लैंड का रोडमैप भी होना चाहिए ना। जो लैब में है वो लैंड में भी तो उतरना चाहिए ना। और जैसे लैब टू लैंड होना चाहिए वैसे ही लैंड पर यूनिवर्सिटी में नहीं गए ऐसे लोगों का अनुभव भी बहुत ज्यादा होता है। औरे जो लैंड का अनुभव है। उसको लैब में भी लाना चाहिए और लैब में वो कैसे आये? रिसर्च को कैसे enrich करे, परंपरागत अनुभव को कैसा करें ये सोचकर हम कदम उठा सकते हैं। इसी तरह, हमारे यहां ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद का हमारा ज्ञान हो उसको चुनौती तो आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन दुनिया के कई देश हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमसे आगे निकल रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि आज के समय में परिणाम और प्रमाण दोनों की जरूरत होती है। हम ये कहें कि भई मैं ये जड़ी–बूटी लेते हुए फायदा होता है, परिणाम मिलता है, लेकिन हम मान के चले और सभी यूनिवर्सिटी के छात्र मेरा कुछ न यहां से सुनकर के जाये चलेगा, दो शब्द मेरे सुनकर के चलके जाइएगा और उस पर मंथन कीजिएगा। हमें परिणाम तो मिल जाते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं और इसलिए हमारे पास परिणाम के साथ–साथ प्रमाण होने चाहिए। हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। हमारे पास उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए, कहां से कैसे बदलाव हुआ है। हम भावना के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते हैं। दुनिया के सामने उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और इसलिए परिणाम होने के बावजूद भी प्रमाण की आवश्यकता आज की विश्व को बहुत जरूरी है। और इसलिए अब हमारी यूनिवर्सिटीज जो परिणाम से हम परिचित हैं लेकिन जिसमें प्रमाण का अभाव है, उन प्रमाण की पूर्ति करने के लिए मैकेनिज्म बनाना, व्यवस्थाएं विकसित करना, परंपराएं विकसित करना ये आप सब साथियों के मदद के बिना होना नहीं है। एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिसर्च का ये काम भी हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं।

हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी ताकत है। चर्चा भी करते हैं लेकिन क्या कोई यूनिवर्सिटी है जिसने इसका

स्टडी किया है कि आखिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या। क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर आया था तब उस दुनिया के उद्देश्य ने किस प्रकार के कदम उठाये थे। वहां की यूनिवर्सिटी कैसे व्यवहार करती थी और उसका बैनिफिट कैसे लिया। बहुत बार हम कहते हैं दोहराते रहते हैं। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावनाओं पर हम क्यों न काम करें, उस सामर्थ्य का उपयोग हम आने वाले 20,25,30 साल के लिए देश को कैसे दे सकते हैं। ऐसे ही, हम देखते हैं अब दुनिया के देशों की स्थिति देखिए समृद्ध से समृद्ध देश भी इस बात से परेशान है कि वहां लोगों की आयु बहुत बढ़ रही है। Ageing (एजिंग) प्रॉब्लम है और युवा पीढ़ी न के बराबर हो रही है। बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों का है। उनको जो दुनिया चलानी है उसको चला नहीं पाते हैं। अब ये चक्र ऐसा है कि इसमें हरेक को आना ही आना है। आज हमारे देश युवा है कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा। इसमें युवा कम होंगे, वृद्ध ज्यादा होंगे वो दिन आने वाले हैं। क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के वृद्धत्व के कारण देश की जो स्थितियां बनी है, उसके solution के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोजें हैं। यूथ का अभाव में वो समस्याओं को समाधान कैसे कर रहे हैं। कौन से ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि चीजें बड़ी smoothly आगे बढ़ रही हैं। ये सारे सोचने का काम मेरी यूनिवर्सिटीज का सहज स्वभाव होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में आपके लिए अभी से मैं मानता हूं रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है और इसके कारण जिन बच्चों को ये प्रोजैक्ट देते हैं उनका एक विजन बनता है। उनको भी नई चीजें समझने का अवसर मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। क्लाइमेट की फील्ड में भी हमारे लोग अगर काम करें तो असीमित संभावनाएं हैं हमारे पास। अब हमारे देश में एक योजना बनाई है CDRI की। क्लाइमेट की स्थिति में हमारा infrastructure ऐसा होना चाहिए जो उसका सामना कर सके। resilient होना चाहिए। अब उस पर हमारे रिसर्च के बिना हम कैसे करेंगे, पहले के जमाने में जो चीजे बनाते थे। तब न इतनी बाढ़ आती थी, न इतनी वर्षा होती थी कुदरत हमारे साथ चलती थी, हम कुदरत के साथ चलते थे। अब वो हमसे उलटा चल रही है, हम उससे उलटा चल रहे हैं और इसलिए हमें इस नए संकट के सामने जीना कैसे है उसको सिखने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आज सारी दुनिया सोलर पॉवर की तरफ बढ़ रही है। भारत भाग्यवान है कि उसके पास तपता हुआ सूरज है। उस तपते हुए सूरज की मालिकी का हम कैसे उपयोग करेंगे। उसके सामर्थ्य को हम हमारे जीवन व्यवस्था का हिस्सा कैसे बनाएं। सोलर पावर को हमारे यहाँ इतना महत्व दिया गया है। सरकार की नीतियों में दिया गया है। लेकिन हम रिसर्च के द्वारा, नए–नए अनुसंधान के द्वारा आज नए युग के हिसाब से नए वैज्ञानिक संसाधनों के साथ इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरूरत लगती है। उसी तरह साथियों, स्वच्छ भारत अभियान हर व्यक्ति के दिल में ये बात अब घर कर गई है। हां भई स्वच्छ भारत के विषय में कोई compromise नहीं होना चाहिए। लेकिन बात वहां से बनती नहीं है। जब तक हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ योजनाएं नहीं बनाते हैं, ये जो कूड़ा कचरा निकलता है, उसका सर्कुलर इकॉनामी क्या हो सकती है, उसका बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ये तो यूनिवर्सिटी रिसर्च करके दे सकती है। हमारे नए–नए लोग होते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। हम वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाएं। हम सर्कुलर इकॉनामी को कैसे मजबूत करें और खासकर लोकल लेवल पर सर्कुलर इकॉनामी जैसे कितने ही क्षेत्र आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। आज देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी नए आत्मविश्वास के साथ नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पोर्टस यूनिवर्सिटी यहां बन रहीं हैं इसलिए बाकी यूनिवर्सिटी के नौजवानों को स्पोटर्स से कोई लेना देना नहीं है, जी नहीं हमारी यूनिवर्सिटी की मैदान शाम को भरे रहने चाहिए। बच्चों को घर भेजने के लिए मेहनत करनी पड़े, ये वातावरण हर यूनिवर्सिटी के मैदान में होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी ये लक्ष्य बना सकती हैं। एक–एक यूनिवर्सिटी तय कर सकती है कि आने वाले वर्षों में मेरी यूनिवर्सिटी कितने गोल्ड मेडल्स ले आएगी, मेरे स्कूल के कितने विद्यार्थी, मेरे कॉलेज के कितने विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी के टारगेट क्यों नहीं होने चाहिए दोस्तों। दुनिया के कितने देश में मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चें खेलने के लिए जाएंगे, मैं उनको कैसे तैयार करूं। उनको exposure मिलेगा वे भी मेरी एक बहुत बड़ी अमानत बन जाएगा। साथियों मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं। अनगिनत संभावनाएं हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके हाथ में अवसर दिया है। जो पिछले वर्षों में हमारे पास नहीं था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण आया है। ये हमारा काम है उसको आगे बढ़ाएं।

स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थीं, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए नई दुनिया बन रही है।

हम सबको याद रखना होगा कि देश के भविष्य निर्माण का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नेतृत्व आप सब साथियों के हाथ में है। मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम में आपके मंथन से निकला अमृत, आपके सुझाव, देश को एक नई दिशा देंगे। जिन नौजवानों के साथ आपका समय बीतता है, उनको वर्तमान के लिए नहीं आने वाले कल के लिए तैयार करना है। अगर आने वाले कल के लिए तैयार करना है तो आपको आने वाले साल के लिए तैयार होना है। अगर आप आने वाले साल के लिए तैयार होते हैं तो आपको institute को आने वाले 100 सालों के लिए तैयार करना है, तब जाकर के इस काम को प्राप्त कर सकते हैं और उसी भाव के साथ आप लोग काशी की इस पवित्र धरती पर हैं। मां गंगा के तट पर विराजमान हैं। सांस्कृतिक पूरी परंपरा हमें नई चेतना और प्रेरणा देने वाली परंपरा है। उस परंपरा में से कुछ न कुछ अमृत बिंदू आपके भी नसीब में आएंगे, जो अमृत बिंदू लेके जाएंगें। वहां जब आप उसको रखोगे वो युवा युवती भी आने वाले अमृतकाल में भारत के उज्जवल भविष्य को गढ़ने के लिए काम आएगी, मैं फिर एक बार विभाग का इस कार्यक्रम की रचना के लिए धन्यवाद करता हूं।

आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त हो : मुर्मू

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रोपदी मुर्मू का शुक्रवार को प्रदेश में आयोजित बैठक में राजग के घटक दलों के सांसदो व विधायकों ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए समर्थन व्यक्त किया। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल (एस), निषाद पार्टी के सांसदो व विधायकों की बैठक में श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में समर्थन की अपील की। श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के साथ लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, केन्द्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्रीमती स्मृति ईरानी, डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री बृजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरूण सिंह, श्री विनोद तावड़े, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. संजय निषाद, संसदीय कार्यमंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना उपस्थित रहे। स्वागत और अभिनंदन के पश्चात बैठक में करतल ध्वनि से श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में समर्थन किया गया।

श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वेदों की जननी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान और महानिर्वाण प्रदान करने वाली, गंगा जमुना की पावन धारा से आह्लादित पवित्र उत्तर प्रदेश की भूमि को नमन।

उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वाधीनता आंदोलन का यह प्रमुख केंद्र रहा है। आजादी के अमृत वर्ष में आज चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडेय, बेगम हजरत महल, मंगल पांडेय, गणेश शंकर विद्यार्थी, राम मनोहर लोहिया जैसे महान सपूतों की जीवंत स्मृतियां प्रवाहमान हो उठी हैं।

श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इस प्रदेश ने देश को 08 प्रधानमंत्री दिए हैं। यह अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल जी की भूमि है। श्रद्धेय अटल जी ने यहीं पांचजन्य का संपादन किया था। विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि यही उत्तर प्रदेश है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली एक महिला आज आपके सामने समर्थन मांगने आई है। मैंने अभाव के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। कमजोर वंचित तबके और जनजातीय समाज के लिए अजीवन मैंने कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त होगा। यह उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट परंपरा का निदर्शन है। मैं प्रदेश के हर सांसद, विधायक से सकारात्मक सहयोग का आह्वान करती हूं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत भाषण के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों की ओर से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत–अभिनंदन करता हूँ।

उन्होंने कहा कि हम सब आभारी हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के, जिन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए जनजातीय समाज की एक मातृशक्ति के रूप में सर्वसम्मत चेहरा दिया है। इस निर्णय को न केवल एनडीए के घटक दलों ने सकारात्मक भाव के साथ स्वीकार किया है, बल्कि दलीय सीमाएं टूटती हुई दिख रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की बेटी का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए निर्वाचन पूरी दुनिया को भारत के सशक्त लोकतंत्र का अहसास कराएगा।

प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने श्रीमती द्रोपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कहा कि श्रीमती द्रोपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी विश्व के लोकतंत्र को एक संदेश है। शून्य से शिखर तक की यात्रा, पारिवारिक, सामाजिक व राजनैतिक जीवन में स्थापित किए गए आदर्श भारतीय लोकतंत्र के लिए विश्वास व आदर्श की धरोहर है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रोपदी मुर्म शुक्रवार सायं 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, अपना दल (एस) के नेता आशीष पटेल, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 संजय निषाद, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरूण, प्रदेश महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनीष दीक्षित ने उनका स्वागत किया।

एयरपोर्ट के बाहर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गो, समाजिक संगठनों के लोगो ने श्रीमती द्रोपदी मुर्मू का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। ढोल नगाड़ो के साथ लोक कलाकारों ने उत्तर प्रदेश के सभी अंचलो की लोककलाओं व लोक संगीत से श्रीमती मुर्मू का अभिनंदन किया।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार

भाजपानीत एनडीए ने 21 जून, 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल और ओडिशा में मंत्री रही हैं।

श्रीमती मुर्मू ने 24 जून को अपना नामांकन दाखिल किया, राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी।

अगर वह चुनी जाती हैं, तो वह भारत की पहली जनजातीय और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी।

श्रीमती मुर्मू लगातार बाधाओं को पार कर नये अध्याय लिख रही हैं, वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने 2015 से 2021 तक अपनी सेवाएं दीं।

श्रीमती मुर्मू ने ओडिशा के एक पिछड़े जिले मयूरभंज गांव में एक गरीब जनजाति परिवार से आने के बावजूद अपनी पढ़ाई को पूरा किया। वह रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में शिक्षिका थीं। उनका जन्म 20 जून, 1958 को हुआ था और उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज में पढ़ाई की।

उन्होंने रायरंगपुर एनएसी के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। श्रीमती मुर्मू ने 2000 से 2004 तक रायरंगपुर क्षेत्र का ओडिशा विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने परिवहन और वाणिज्य, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री के रूप में कार्य किया। 2004 से 2009 तक वह फिर से ओडिशा विधानसभा की सदस्य रहीं। 2007 में ओडिशा विधानसभा ने उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार' से सम्मानित किया।

1979 और 1983 के बीच उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 1997 में प्रदेश एसटी मोर्चा की उपाध्यक्ष सहित भाजपा के कई संगठनात्मक पदों पर कार्य किया। वह 2006 से 2009 तक भाजपा के ओडिशा एसटी मोर्चा की अध्यक्ष रहीं। 2002 से 2009 तक वे भाजपा एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहीं।

श्रीमती मुर्मू 2013 से 2015 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्य रहीं और वह 2010 और 2013 में मयूरभंज (पश्चिम) की भाजपा जिलाध्यक्ष रहीं।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाजसेवा एवं गरीबों, दलितों के साथ-साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की सर्वोत्तम राष्ट्रपति साबित होंगी। लाखों लोग, विशेष रूप से वे जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, उन्हें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से बहुत ताकत मिलती है। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समृद्ध प्रशासनिक अनुभव, निःस्वार्थ समाजसेवा का इतिहास और समाज के उत्थान के लिए काम करने का अथक उत्साह, उन्हें देश के एक महान राष्ट्रपति के तौर पर स्थापित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में उन्हें एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करना सम्मान की बात है। उनका व्यक्तित्व हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और हम सभी के लिए आदर्श है। देश के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है और उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की विशेषज्ञता है जो हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद होगी। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान की दिशा में उनके प्रयासों को भी व्यापक रूप से समर्थन मिला है।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाजपा ने परिवारवाद से ऊपर राष्ट्रवाद को बढ़ाया : योगी

भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देश दुनिया में सबसे बड़े राजनैतिक दल के रूप में बीजेपी उभर कर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों में विश्वास पैदा किया है। परिवारवाद की नीतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि ये टीम वर्क का परिणाम है कि बीजेपी ने हर चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है चाहे फिर वो पंचायत चुनाव हो विधानपरिषद, विधानसभा या हाल में हुए दो उपचुनाव हो। बीजेपी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने असंभव को संभव करके दिखाया है।

सीएम योगी ने कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। यहां वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति नहीं होती बल्कि राष्ट्रवाद पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति का पैमाना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति से होगा। जनजातीय लोगों के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल होगा जब उनके बीच में रही एक साधारण सी महिला देश के सबसे बड़े पद की बागडोर संभालेंगी।

प्रदेश पदाधिकारी बैठक

प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि भूखे पेट रहकर कालजयी मनीषियों ने पार्टी के लिए सर्वस्व अर्पण करते हुए तपस्या की , तब आज पार्टी यहां तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि वह स्वप्न जो मनीषियों ने देखे वे अभी साकार नहीं हुए है। अभी हमें अपनी विचारधारा व प्रतिबद्धता को सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी बनाने के लिए और अथक परिश्रम करना है। इसलिए तप, तपस्या और त्याग जीवन का मूलमंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जातिवाद, क्षेत्रवाद व परिवारवाद से हटकर राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ रहा है। हम सभी को मोदी जी व योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास का मंत्र लेकर जन–जन की दहलीज पर बार–बार पहुंचाना है।उन्होंने रामपुर व आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा की विजय पर सभी को बधाई दी।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल ने संगठन की आगामी कार्ययोजना को बैठक में रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक के अनुवर्तन में प्रदेश की बैठक और प्रदेश के बाद जिला बैठकों की परम्परा के क्रम में आज प्रदेश की बैठक हुई है और आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में जिला बैठकें आयोजित की जाएगीं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पन्ना प्रमुखों की संरचना पर फिर एक बार नए सिरे से काम किया जाना है।

श्री बंसल ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम रविवार को जन–जन की बात से 'मन की बात' कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ पर समूह के साथ सुनना और उससे अधिक से अधिक नागरिको को जोड़ने का काम भी करना है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत भाजपा की दृष्टि से कमजोर 22 हजार बूथों पर सांसदों व विधायको द्वारा सम्पर्क का कार्य चल रहा है। इसे और अधिक गति देना है।

जिन लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के सांसद नहीं हैं प्रदेश के ऐसे 14 लोकसभा क्षेत्रों में आज 8 जुलाई से केन्द्रीय मंत्रियों के प्रवास प्रारम्भ होगें। उन्होंने कहा कि जिला व मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम हो चुके है। आगामी 21 अगस्त के बाद प्रदेश का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात् 15 अगस्त तक मोर्चों के प्रशिक्षण सम्पन्न होगें।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पार्टी स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सभी परिवारों में तिरंगा झंडा पहुंचाने का अभियान प्रारम्भ करेगी। पार्टी प्रदेश के हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा फहरा कर आजादी के अमृत महोत्सव को अविस्मणीय बनाकर राष्ट्र प्रेम का संचार करेगी।

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में पारित किए गए आर्थिक प्रस्ताव को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने प्रदेश बैठक में प्रस्तुत किया तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा ने तेलंगाना की स्थिति तथा भाजपा की नीति पर राष्ट्रीय कार्यसमिति के पटल पर रखे गए वक्तव्य को बैठक के पटल पर प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय मंत्री श्री हरीश द्विवेदी ने राजनैतिक प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय मंत्री श्री विनोद सोनकर ने राष्ट्रीय कार्यसमिति का वृत्त रखते हुए राष्ट्रीय कार्यसमिति की रूपरेखा व उद्देश्यों को रेखांकित किया।

पार्टी की विगतदिनों राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 2 और 3 जुलाई को (तेलंगाना) में सम्पन्न हुई । भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय कार्यसमिति में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी गई । बैठक के साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों व अभियानों के विषय में भी चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी श्री राधामोहन सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व बृजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल जी, सह संगठन मंत्री श्री कर्मवीर जी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने किया।

संगठनात्मक गतिविधियां

असम में भाजपा ने केएएसी की सभी 26 सीटें जीतीं

कांग्रेस नहीं खोल पायी खाता

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 12 जून, 2022 को घोषित असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद् (केएएसी) के परिणामों मे सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इन 26 सीटों के लिए 08 जून को मतदान हुआ था।

कुल सीट	भाजपा	कांग्रेस	अन्य
26	26	0	0

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा की प्रचंड जीत की सराहना की और लोगों को आश्वासन दिया कि पार्टी असम की प्रगति के लिए काम करती रहेगी। "कार्बी आंगलोंग में ऐतिहासिक परिणाम! मैं लोगों को भाजपा में उनके निरंतर विश्वास प्रकट करने के लिए धन्यवाद देता हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम असम की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयास उत्कृष्ट रहे हैं। उन्हें प्रणाम!"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, "केएएसी चुनावों में इस शानदार जीत के लिए सभी असम भाजपा के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को बधाई। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के विजन में लोगों के विश्वास और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस जनादेश के लिए लोगों को धन्यवाद।"

मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "हम लगातार दूसरी बार केएएसी चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कार्बी आंगलोंग के लोगों के समक्ष नतमस्तक हैं।" श्री सरमा ने कहा कि शहरी निकाय और जीएमसी चुनावों में जीत के बाद, यह विशाल जीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विश्वास' के विजन में जनता के भरोसे को दिखाता है।

उल्लेखनीय है कि सितंबर 2021 में कार्बी आंगलोंग जिले के पांच उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद केएएसी के लिए यह पहला चुनाव था। पिछले साल 'कार्बी आंगलोंग समझौते' की मोदी सरकार की इस ऐतिहासिक पहल के बाद 1,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, साथ ही कार्बी क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपये के 'विशेष विकास पैकेज' की घोषणा भी हुई थी। ■

महाराष्ट्र विधान परिषद् चुनाव में भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की

महा विकास अघाड़ी गठबंधन को एक बड़ा झटका देते हुए भाजपा ने 20 जून, 2022 को संपन्न हुए महाराष्ट्र विधान परिषद् के चुनाव में पांच सीटें जीतीं, जबकि सत्तारूढ़ शिवसेना और राकांपा को दो-दो सीटें मिलीं। भाजपा प्रत्याशी श्री प्रवीण दारेकर, श्री राम शिंदे, श्री श्रीकांत भारतीय, श्री उमा खापरे और श्री प्रसाद लाड ने जीत दर्ज की।

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ गठबंधन को क्रॉस वोटिंग के बाद हार का सामना करना पड़ा। सत्तारूढ़ एमवीए के लिए दो सप्ताह के भीतर यह लगातार दूसरी हार है। इससे पहले भाजपा ने 10 जून को राज्यसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की थी।

भाजपा ने पांच उम्मीदवार जबकि एमवीए ने 10 एमएलसी सीटों के लिए छह उम्मीदवार उतारे। संख्या कम होने के बावजूद भाजपा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही।

जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हमारे सभी पांच उम्मीदवार चुनकर आये हैं। राज्यसभा में भाजपा को 123 वोट मिले। परिषद् चुनाव में हमें 134 वोट मिले। हमारे पांचवें उम्मीदवार को जीताने के लिए हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन फिर भी हमें कांग्रेस के दो उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले।" ■

अग्निपथ योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए 'अग्निपथ योजना' को दी मंजूरी

संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत चार साल के लिए अग्निवीर नामांकित किए जाएंगे। तीन सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक मासिक पैकेज तथा चार साल की कार्यावधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना को 'अग्निपथ' कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को 'अग्निवीर' कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है।

'अग्निपथ योजना' सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा, जो समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके वर्दी धारण करने के प्रति इच्छुक हो सकते हैं, जो समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं और समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति की पूर्ति करते हैं। जैसाकि सशस्त्र बलों के लिए यह सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगा और 'जोश' और 'जज्बा' का एक नया संसाधन प्रदान करेगा, साथ ही साथ एक अधिक तकनीकी जानकार सशस्त्र बलों की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा, जो वास्तव में समय की आवश्यकता है।

यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4-5 वर्ष कम हो जाएगी।

राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के युवाओं के लिए एक अल्पकालिक सैन्य सेवा के लाभांश बहुत अधिक हैं। इसमें देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है।

यह तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। नीति, जो तत्काल प्रभाव से लागू होती है, इसके बाद तीनों सेनाओं के लिए नामांकन को नियंत्रित करेगी।

अग्निवीरों को लाभ

अग्निवीरों को तीन सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। चार साल की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका योगदान शामिल होगा जिसमें उस पर अर्जित ब्याज और सरकार से उनके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	अनुकूलित पैकेज (मासिक)	हाथ में (70%)	अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान (30%)	भारत सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान
	सभी आंकड़े रुपये में (मासिक अंशदान)			
प्रथम वर्ष	30000	21000	9000	9000
दूसरा वर्ष	33000	23100	9900	9900
तीसरा वर्ष	36500	25580	10950	10950
चौथा वर्ष	40000	28000	12000	12000
अग्निवीर कॉर्पस फंड में चार साल बाद कुल योगदान			5.02 लाख रुपये	5.02 लाख रुपये
4 साल बाद बाहर निकलने पर	11.71 लाख रुपये सेवा निधि पैकेज के रूप में (उपरोक्त राशि पर लागू ब्याज दरों के अनुसार संचित ब्याज सहित) का भी भुगतान किया जाएगा।			

'सेवा निधि' आयकर से छूट दी जाएगी। ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति प्रदान की जाएगी। चार साल के इस

कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं।

प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उनके अद्वितीय बायोडाटा का हिस्सा बनने के लिए एक प्रमाणपत्र में मान्यता दी जाएगी। अग्निवीर अपनी युवावस्था में चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से भी खुद को बेहतर बनाने के अहसास के साथ परिपक्व और आत्म-अनुशासित होंगे।

अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे, वे निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काफी लाभदायक होंगे। इसके अलावा, लगभग 11.71 लाख रुपये की सेवा निधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए होता है।

सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्षों की अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी और भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में उनके समकक्ष और समय-समय पर संशोधित भारतीय वायु सेना में नामांकित गैर-लड़ाकू सेवा के मौजूदा नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

यह योजना सशस्त्र बलों में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करके और अधिक युवा और तकनीकी रूप से युद्ध लड़ने वाले बल को बढ़ावा देगी।

लाभ

- सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार।
- युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर।
- सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान।
- अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज।
- अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर।
- सभ्य समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता।
- समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर और जो युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं।

नियम एवं शर्तें

अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को चार साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नामांकित किया जाएगा। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे, जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। सशस्त्र बलों द्वारा समय-समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर चार साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

इन आवेदनों पर उनकी चार साल की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25 प्रतिशत तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा।

नामांकन 'ऑल इंडिया ऑल क्लास' के आधार पर होगा और पात्र आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होगी। हालांकि, पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एकबारगी छूट देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। ■

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 15 जून को 'अग्निपथ योजना' में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया।

गृह मंत्री कार्यालय ने ट्वीट्स के ज़रिए कहा कि 'अग्निपथ योजना' युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए श्री नरेन्द्र मोदी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पुलिस बल में सेवानिवृत्त 'अग्निवीरों' को प्राथमिकता देगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेवानिवृत्त 'अग्निवीरों' को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्रीजी के मंशानुरूप 'अग्निपथ योजना' युवाओं को राष्ट्र व समाज की सेवा हेतु तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार आश्वस्त करती है कि 'अग्निवीरों' को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि 'अग्निपथ योजना' के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापिस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने अगले डेढ़ साल में 10 लाख लोगों की भर्ती का दिया निर्देश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा कि वे 'मिशन मोड' में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 14 जून को इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देश के लिए उनका धन्यवाद किया। एक ट्वीट के ज़रिए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए भारत का आधार उसकी युवा शक्ति है, जिसको सशक्त बनाने के लिए मोदीजी निरंतर कार्यरत है। मोदीजी द्वारा सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने का निर्देश युवाओं में नयी आशा और विश्वास लायेगा। ■

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 45 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3,39,225 करोड़ रुपये हुआ

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अग्रिम कर संग्रह 1,01,017 करोड़ रुपये रहा जो 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित करता है तथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 30,334 करोड़ रुपये के बराबर के रिफंड जारी किए गए

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 16.06.2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रदर्शित करते हैं कि पिछले वर्ष की समान अवधि के 2,33,651 करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध संग्रह 3,39,225 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के संग्रह के मुकाबले 45 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी प्रदर्शित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में शुद्ध संग्रह (16.06.2022 तक) ने वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि के दौरान 171 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कराई, जब शुद्ध संग्रह 1,25,065 करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि के मुकाबले 103 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित की जब शुद्ध संग्रह 1,67,432 करोड़ रुपये था।

3,39,225 करोड़ रुपये (16.06.2022 तक) के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1,70,583 करोड़ रुपये (नेट ऑफ रिफंड) का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) तथा 1,67,960 करोड़ रुपये (नेट ऑफ रिफंड) सेक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आय कर (पीआईटी) शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (रिफंडों के लिए समायोजित करने से पूर्व) पिछले वर्ष की समान अवधि के 2,64,382 करोड़ रुपये की तुलना में 3,69,559 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के संग्रह की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है। इसमें 1,78,215 करोड़ रुपये के सेक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) सहित 1,90,651 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) तथा व्यक्तिगत आय कर (पीआईटी) शामिल है।

गौण शीर्ष वार संग्रह में 1,01,017 करोड़ रुपये का अग्रिम कर, 2,29,676 करोड़ रुपये का स्रोत पर कर कटौती, 21,849 करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर, 10,773 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर, 5,529 करोड़ रुपये का वितरित लाभ कर तथा 715 करोड़ रुपये का अन्य गौण शीर्षों के तहत कर शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए अग्रिम कर संग्रह 1,01,017 करोड़ रुपये का है, जबकि इससे ठीक पहले के वित्त वर्ष की समान अवधि में अग्रिम कर संग्रह 75,783 करोड़ रुपये का रहा था जो 33 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी प्रदर्शित करता है। इसमें 78,842 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) तथा 22,175 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आय कर (पीआईटी) शामिल है। इस राशि में वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि बैंकों से अभी और जानकारी प्राप्त होनी है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए (16.06.2022 तक) टीडीएस संग्रह 2,29,676 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे ठीक पहले के वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 1,57,434 करोड़ रुपये रहा था, जो लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्व-आकलन कर संग्रह (16.06.2022 तक) 21,849 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे ठीक पहले के वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15,483 करोड़ रुपये रहा था जो 41 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 30,334 करोड़ रुपये के बराबर के रिफंड भी जारी किए गए हैं। ■

समष्टि का सामूहिक स्वरूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय

गतांक का अंतिम भाग...

पुरुषार्थ की कल्पना मनुष्य को करनी आवश्यक है। ऐसे चार तरह के कार्य अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये चार पूर्ण होते रहे, तो ही सामाजिक जीवन सफल होता है। अर्थः जीवनावश्यक सब चीजें प्राप्त करने के लिए राज्य आवश्यक है। और इसका घनिष्ठ संबंध है। राजा नहीं, सेना नहीं, पुलिस नहीं तो जीवन का क्या होगा? गुलाम बनेंगे। अर्थहीन, राज्यहीन अवस्था बन जाएगी। इसलिए साधन जुटाना चाहिए। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ आवश्यक कामनाओं की तृप्ति के लिए अर्थ की जरूरत होती है। अर्थ, काम पुरुषार्थ का साधन है और काम पुरुषार्थ के साथ अर्थ है। अर्थ का उद्देश्य अपनी आशाओं का 'काम' तृप्त करने के लिए। उदाहरण, पेट भरने के लिए चावल, कपड़े के लिए कपास निर्माण करते हैं। परंतु आशाओं पर बंधन चाहिए, वही धर्म। गेहूं, चावल, द्राक्ष, ये आहार के लिए हैं। मद्य तैयार करने के लिए नहीं। यानी काम-तृप्ति धर्म विरोधी नहीं रहनी चाहिए। दूसरे को देकर खाने में मन को शांति मिलती है और यह समझकर बताने वाली बुद्धि होती है। जिन्होंने अनुभव लिया है, उनकी बुद्धि-ज्ञान ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। अपने सुख के नियम ऐसे अनुभवी लोगों ने खोज निकाले हैं। बीमार आदमी को उपचार के नियम आयुर्वेद ने बताए। उसी प्रकार जीवन के सब नियम उन्होंने बनाकर रखे। ये नियम निर्माण नहीं कर सकते, तो उनकी खोज करनी पड़ती है। ये सब नियम धर्म-कार्य के लिए हैं, आख़िर में मोक्ष दिलाने के लिए हैं। मोक्ष यानी परम आनंद की स्थिति ।

यह सब मिलाकर राष्ट्र होता है। व्यक्ति और समाज यानी सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों भी महत्त्वपूर्ण हैं। समाज कितना भी छोटा हुआ, तो भी उसमें दो बाजू रहती ही हैं। उन दोनों को, दो बाजू को अलग नहीं कर सकते।

न्याय-अन्याय का विवेक

पाश्चात्यों में आर्थिक मानव' की मात्र कल्पना की गई है। अर्थशास्त्र में चार से पांच रुपया ज्यादा है, लेकिन न्यायपूर्ण और प्रामाणिकता से मिले चार रुपए, अन्याय से मिले पांच रुपए से अच्छे रहते हैं। उसकी क़ीमत ज्यादा है। आज अपनी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इसका कारण यह है कि यह जो न्याय, अन्याय का विवेक है, उसको हम भूल बैठे हैं। प्रजातंत्र में 'राजकीय-मानव' की मात्र कल्पना है। इस प्रकार एक एक बात का अलग-अलग विचार पाश्चात्यों ने किया है, उससे परस्पर विरोध निर्माण होने से एक-दूसरे के साथ सहकार नहीं, उनका तर्क परस्पर मेल नहीं खाता।

अपने यहां सब बातों का समग्र विचार किया गया है। अंतिम हित निर्माण करने में कौन समर्थ रहते हैं, बीमार आदमी को कौन सी औषधि देनी चाहिए। इसका तय जनता, सरकार, न्यायालय इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। उसका तय केवल वैद्य ही कर सकता है। वैद्यकीय शास्त्र में यह एक धर्म, नियमों का ज्ञान, वही अंतिम अधिकारी होता है। सब क्षेत्रों में यही नियम लागू है। ये सब मिलकर धर्म होता है। जन्म होते ही माता के स्तन में दूध तैयार रहता है। जन्म होते ही प्राणी स्तर पर रहे व्यक्तियों का समाज पोषण करता है। उसे ज्ञान देता है, अन्यान्य संस्कार करता है और उसको मनुष्य बनाता है। सब सामाजिक संस्थाओं का यह करणीय कार्य है। कुटुंब, पंचायत, जाति और अनिवार्य पक्ष में राज्य, ये सब व्यक्ति को सहायता देनेवाले आधार हैं। सबके आख़िर में राज्य है। लेकिन आज के समाजवाद में सबसे प्रथम और आख़िर में भी राज्य है।

व्यक्ति को निष्काम-कर्म करना चाहिए। पितृऋण, मातृऋण, देशऋण, देवऋण आदि सब ऋण चुकाने चाहिए और इसलिए उसको काम मिलना चाहिए। कर्म के अनुसार फल मिलता है। वह फल भी व्यक्ति को समाज को समर्पण कर देना चाहिए।

किसान खेती करता है और आख़िर में निर्माण हुई फ़सल समाज को अर्पण करता है। इसी को ही यज्ञ कहते हैं। उस फ़सल का समाज समानता से वितरण करता है। जैसे मां अपने चार बेटों में कोई भी चीज़ समानता से और आत्मीयता से बांटती है। समाज यानी कुटुंब, जाति, पंचायत और शासन। शासन एक ही नहीं। व्यक्ति कमाया हुआ धन मां के पास देता है। और मां फिर चारों भाइयों को ज़रूरत के अनुसार धन देती है। कमाया हुआ धन कोई पंचायत को, कोई राज्य को कर के रूप में देते हैं। इस धन का आगे राज्य क्या करेगा? स्कूल, दवाख़ाना आदि आवश्यक बातें, मां के जैसी आत्मीयता से समाज को देता है। इसी को यज्ञ-चक्र कहते हैं। समुद्र से भाप, बादल, बरसात, नदी, समुद्र यह है उसी प्रकार व्यक्ति समाज का परस्पर सुखपूरक रीति से चक्र फिरता है। कर्म, फल, यज्ञ, यह चक्र जहां है, वहीं समाज ठीक तरह से चलता है। समाज में सुव्यवस्था रहती है।

पश्चिम ने बांटा

पाश्चात्यों ने एक समुच्चय के रूप में जीवन का समग्र विचार न करते हुए उसको अनेक हिस्सों में बांटा है और जीवन का टुकड़े-टुकड़े

में विचार किया है। उदाहरणतः, पाश्चात्य पद्धति से रोगों का निदान करके उस पर इलाज होता है, उसमें व्यक्ति के शरीर का विचार नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में व्यक्ति के संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। रोगों का निदान करके शरीरानुकूल इलाज किया जाता है। सबको एक ही दवा नहीं दी जाती। पाश्चात्यों की भोजन-पद्धति, भोजन करने का तरीक़ा भी खंड-खंड में है। हम चावल दाल मिलाकर खाते हैं। लेकिन पाश्चात्यों को सब मिलाकर कैसे खाना है, मालूम नहीं। वे अलग-अलग चीजें अलग-अलग खाते हैं। हमने जीवन को संपूर्ण रूप से देखा है। केवल आर्थिक कार्यक्रम लेकर कोई चले तो उसकी उन्नति नहीं होती। परीक्षा में विद्यार्थी सब विषयों में पास हुआ तो ही उत्तीर्ण होता है। केवल एक विषय में पास होकर नहीं चलेगा। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन सब में पास हुए तो ही जीवन सफल और यशस्वी बनता है। व्यक्ति और समाज के हित का सदैव विचार चाहिए। ज़ोर से भागना भी है तो पैर को साथ देनेवाली दृष्टि भी चाहिए। आंख नहीं और तेज़ दौड़ेगा, तो वह कहां जाकर टकराएगा?

अपने शरीर के अंदर ताक़त यानी अपना प्राण है। वैसे समाज का प्राण यानी विराट् है। राष्ट्र के अंदर अगर विराट् है, संगठित शक्ति, क्षात्र तेज है तो ही राष्ट्र ठीक रहता है। यदि निरोगी सशक्त अवस्था में है तो शरीर के सब अवयवों में शक्ति रहती है यदि यही दुर्बल है तो राष्ट्र दुर्बल रहता है, विकृतियां पैदा होती हैं। रा.स्व. संघ समाज की वह प्राणशक्ति है। वही सब क्षेत्रों में कार्य कर रही है। हृदय पैर की छोटी उंगली की भी चिंता करता है। उसी तरह लद्दाख पर हमला हुआ तो यहां हमें दुःख होता है। संघ का कार्य विराट् को मज़बूत बनाना है।

विराट् को जाग्रत् करना यानी संगठन का कार्य करना है। टुकड़ा-पद्धति से यह कार्य नहीं होगा। इसलिए हम पश्चिम के पद-चिह्नों पर चलना बंद करें और अपनी पद्धति का ज्ञानदीप आगे लें। इससे पाश्चात्यों को भी मार्ग-दर्शन करने का सामर्थ्य अपने में आएगा। हम पश्चिम को अपनी एकात्म जीवन-पद्धति, एकात्म मानवतावाद देना चाहते हैं। हम अपने रास्ते पर चलते हुए एक आदर्श जीवन—

'एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम् सर्वमानवाः ॥

ऐसा एक आत्मविश्वास का भाव लेकर हम कार्य करके दिखाएंगे तो पाश्चात्य राष्ट्र अपने पीछे जरूर आ जाएंगे। इसलिए इस मार्ग का रक्षण करना चाहिए। हमारी संगठित शक्ति से धर्म का रक्षण करते हुए परम वैभव प्राप्त करना है, ऐसी अपनी प्रार्थना है। उसको हम हर दिन कहते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि भगवान् से केवल खीर मांगने से काम नहीं चलेगा। खीर हज़म करने की सामर्थ्य, जीर्ण शक्ति भी हमें चाहिए। शरीर स्वस्थ रहा तो कोई सी भी चीज़ जीर्ण होती है। अपनी कार्य पद्धति में अपने जीवनादर्शों का रक्षण करनेवाली शक्ति का विन्यास होता है। वृद्धि होती है। विराट् जाग्रत् होता है। उससे राष्ट्र का परम वैभव मिलाने की सिद्धता होती है। इसलिए यह संगठन का कार्य करणीय है। इसे स्वीकार करें। (समाप्त)

(–संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्गः बंगलौर, 27 मई, 1965)

सभी 36 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हुई 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना

गत 21 जून को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार असम 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया। इसके साथ, ओएनओआरसी योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा क्रियान्वित हो गई है। कोविड–19 महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान ओएनओआरसी योजना ने एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह देश में अपनी तरह की एक विशेष नागरिक केंद्रित पहल है जिसे अगस्त, 2019 में शुरू किए जाने के बाद से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए बहुत कम समय में तेजी से लागू किया गया।

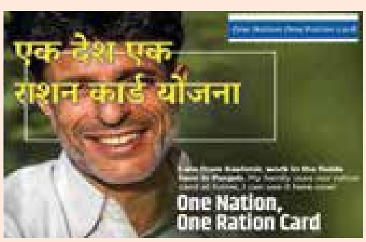

इस लाभार्थी केंद्रित उच्च प्रभावी योजना का उद्देश्य सभी एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं पर भी अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने मौजूदा राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने अधिकार के सब्सिडी वाले खाद्यान्न (आंशिक या पूर्ण) को निर्बाध रूप से उठा सकते हैं। यह लाभार्थियों के परिवार और सदस्यों को उनकी पसंद के एफपीएस से अपने मूल स्थान या किसी और जगह पर भी उसी राशन कार्ड पर शेष/आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाता है।

श्रद्धांजलि: डॉ. मुकर्जी जन्मदिवस (6 जुलाई)

राष्ट्रीयता के उद्घोषक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

(6 जुलाई, 1901 – 23 जून, 1953)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी राष्ट्रीयता के उद्घोषक एवं प्रखर विद्वान् थे।

डॉ. मुकर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को एक प्रसिद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के एक जाने-माने व्यक्ति थे। डॉ. मुकर्जी ने कलकत्ता से स्नातक डिग्री प्राप्त की। वे 1923 में सीनेट के सदस्य (फैलो) बन गये। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन् 1924 में कलकता उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में नाम दर्ज कराया। बाद में वे सन् 1926 में 'लिंकन्स इन' में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर बन गए।

33 वर्ष की उम्र में सन् 1934 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा उपकुलपति बने और उन्होंने यह दायित्व 1938 तक संभाला। उन्होंने विश्वविद्यालय में विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और डॉ. एस. राधाकृष्णन को बंगलोर से कलकत्ता प्राध्यापक के नाते आमन्त्रित किया। उन्होंने लगभग 22 विश्वविद्यालयों (जिनमें मद्रास, बनारस, आगरा और दिल्ली विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं) में दीक्षान्त व्याख्यान दिये। डॉ. मुकर्जी भारत में महाबोधि समाज के संस्थापक अध्यक्ष थे।

महात्मा गांधी के सुझाव पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें स्वातन्त्र्योत्तर भारत की प्रथम अन्तरिम केन्द्रीय सरकार में उद्योग और आपूर्ति मन्त्री बनाया। उन्होंने सिन्दरी उर्वरक कारखाना, भाखड़ा नांगल बांध और भिलाई इस्पात उद्योग को स्वीकृति दी। 6 अप्रैल, 1950 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने 1949 में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री लियाकत अली खां से की गई दिल्ली सन्धि के विरोध में मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। वे पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले लाखों हिन्दू शरणार्थियों की दुर्दशा के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते थे और उन शरणार्थियों पर राज्य सत्ता समर्थित अत्याचार के विरुद्ध प्रबलता से खड़े हुए।

संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर) से परामर्श कर डॉ. मुकर्जी ने 21 अक्टूबर, 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और सर्वसम्मति से उसके पहले अध्यक्ष चुने गए। भारतीय राष्ट्रध्वज की सम्प्रभुता कश्मीर में स्थापित करने के प्रयास में उन्होंने मई, 1953 में कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने की घोषणा की और एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की मांग को लेकर कश्मीर में प्रवेश किया। 11 मई 1953 को लखनपुर में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और श्रीनगर की एक जेल में कारावद्ध रखा। जहां 23 जून, 1953 को उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कमल संदेश भारत मां के इस महान सपूत व भारतीय जनसंघ के संस्थापक को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ■

भारतीय राष्ट्रध्वज की सम्प्रभुता कश्मीर में स्थापित करने के प्रयास में उन्होंने मई, 1953 में कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने की घोषणा की और एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की मांग को लेकर कश्मीर में प्रवेश किया। 11 मई 1953 को लखनपुर में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और श्रीनगर की एक जेल में कारावद्ध रखा

राजनीतिक और सामाजिक न्याय के लिए किसी देश का विघटन आवश्यक नहीं है, न ही पहल, बुद्धिमत्ता और प्रेरणा देनेवाले वर्ग का विनाश या अपमान। बल्कि सभी के लिए अवसर की समानता, आत्मनिर्भर होने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की जरूरत होती है, जिसे सभी जाति या पंथ के लोगों के साथ साझा किया जा सकता है।

-डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

G-7 शिखर सम्मेलन, जर्मनी

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
जुलाई प्रथम अंक 2022 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी